मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 23 अंक : 8

5 अप्रैल 2023

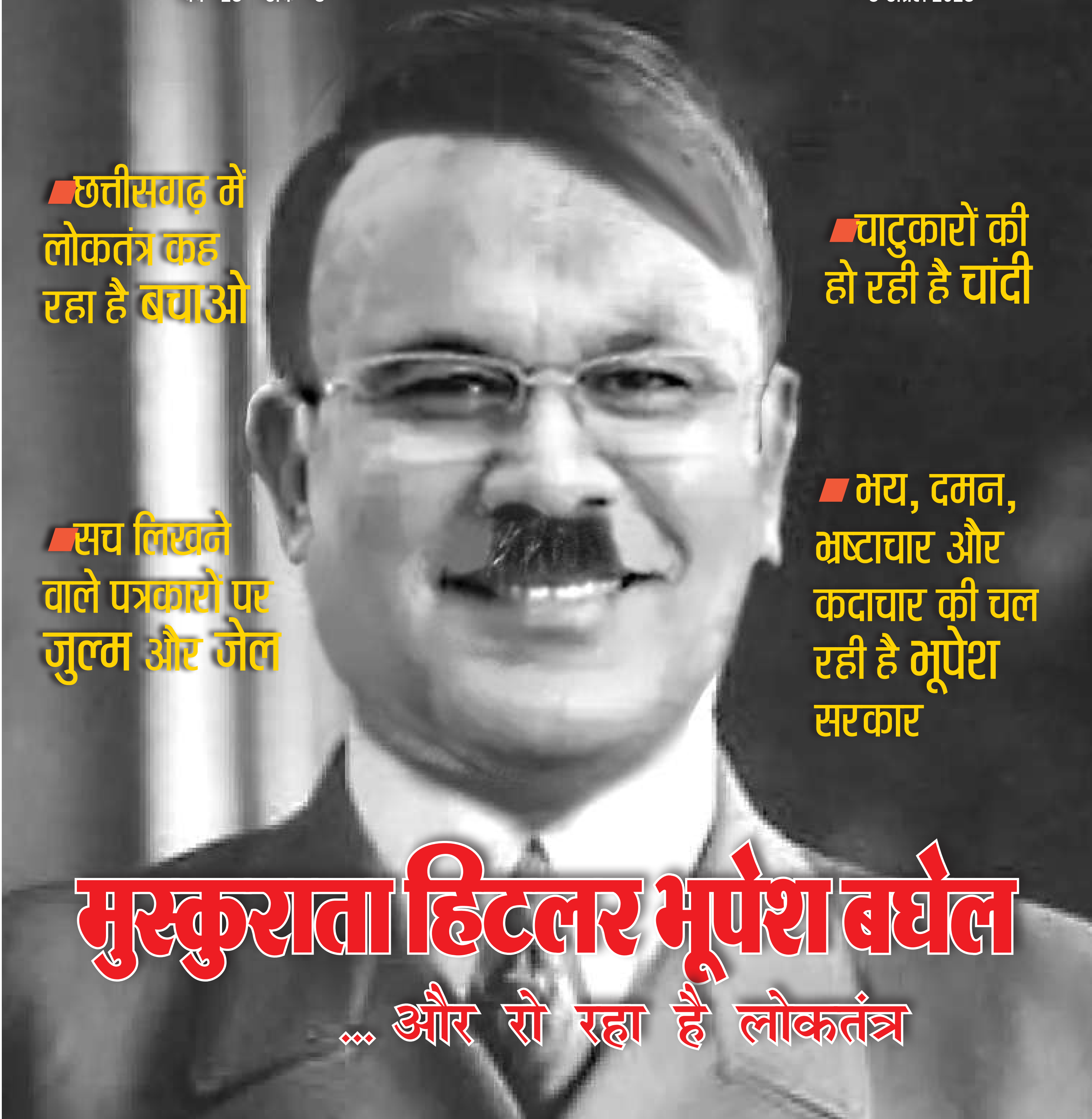

- छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र कह रहा है बचाओ
- चाटुकारों की हो रही है चांदी
- सच लिखने वाले पत्रकारों पर जुल्म और जेल
- भय, दमन, भ्रष्टाचार और कदाचार की चल रही है भूपेश सरकार

मुस्कुराता हिटलर भूपेश बघेल

... और रो रहा है लोकतंत्र

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
उत्तरप्रदेश संवाददाता	वेद कुमार मौर्य

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 23 अंक 08 05 अप्रैल 2023**

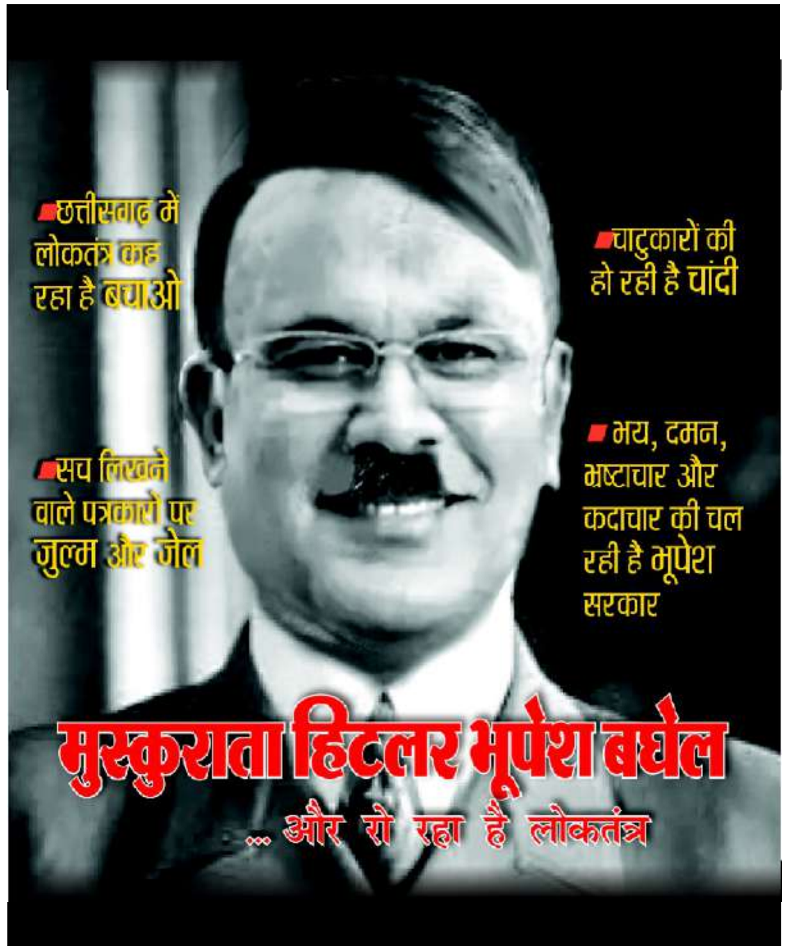

(पृष्ठ क्र.-6)

- क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? 48
- अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा विधानसभा चुनाव 54
- बुंदेलखंड में क्यों काटे जाने हैं 44 लाख पेड़ 58
- Indian Media 61

ऑनलाइन कमाई, हमको बहुत भायी!
ONLINE SATTA

योगी का एक्शन ऐसा कि माफियाओं को सताने लगा गाड़ी पलटने का डर

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार का माफियाओं पर एक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्य नाथ ने कई माफिया, नेता, कारोबारियों, विपक्षी नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार किया गया है। अपने पहले कार्यकाल से ही एक्शन में चल रहे योगी अब दूसरे कार्यकाल में और भी सख्त हो गए हैं। जिसके ही परिणाम है कि प्रदेश में धीरे-धीरे माफियाओं का आतंक खत्म हो रहा है। इसके साथ ही एक समय प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था वह छबि भी समाप्त होने लगी है। पिछले 06 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने राज्य की दिशा बदल दी है। कानून और बुल्डोजर का ऐसा शिकंजा कंसा है कि गुण्डों, माफियाओं का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन का ही नतीजा है कि इन्हें गाड़ी पलटने का डर सताने लगा है। जिसे हम अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की कहानी से समझ सकते हैं। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े हुई हत्या मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसके साथ ही अतीक अहमद राजू पाल की हत्या के एक मामले में प्रयागराज की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली माफियाओं पर भी योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। प्रदेश में खनन माफिया, शराब माफिया, पशु माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, अन्य माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है और इनकी संपत्तियां चिन्हित कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। उत्तरप्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार सरकार के कसते शिकंजे के परिणाम अब दिखने लगे हैं। प्रदेश में पिछले 06 सालों में करोड़ों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की है। इस दौरान माफियाओं को चिन्हित किया गया और उन पर सख्त कार्रवाई पुलिस ने की है। यहां गौर करने वाली बात है कि योगी शासन में पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की छूट मिली हुई है। जबकि पिछली सरकारों में हमने देखा है कि कैसे नेताओं के कारण पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे। बगैर नेताओं की परमीशन के पुलिस किसी पर भी हाथ नहीं डाल पाती थी। जिसका नतीजा यह होता था कि आम या खास में पुलिस का खौफ ही नहीं रहता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है।

जब उत्तरप्रदेश की राजनीति में अपराधियों का दबदबा हो गया तो उन्हें गुंडागर्दी करने से कौन रोक सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेंड को बदल दिया है। प्रयागराज में बुलेट से खूनी खेल खेलने वाले अपराधियों को पनाह देने वालों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश में आज भी अपराधियों की जाति देखी जाती है। यहां वर्षो तक जाति के आधार पर माफिया को संरक्षण मिलता था। पहले जातियों का समर्थन हासिल करने के लिए राजनैतिक दलों ने माफिया का सहारा लिया। फिर जातियों के आधार पर ताकतवर बनने वाले बाहुबली-अपराधी खुद राजनीति में उतरे। चुनाव लड़कर विधायक और सांसद बने। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीतियों से पुलिस को हिम्मत और ताकत मिली। पहले पुलिस अपराधियों से डरती थी। लेकिन अब अपराधी यूपी पुलिस से थर-थर कांपते हैं।

निश्चित ही अगर सारे राजनीतिक दल माफियाओं के दुश्मन हो जाएं, गुंडों को टिकट और संरक्षण देना बंद कर दें, अपनी पार्टियों से आपराधिक तत्वों को निकाल बाहर करें तब ना तो गाड़ी पलटने की जरूरत पड़ेगी और ना बुलडोजर चलाने की। यह भी सच है कि अगर माफियाओं के बीच डर पैदा करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो कानून और व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता था। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियों की चर्चा सारे देश में हो रही है और जनता को भी पसंद आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योगी राज में उत्तरप्रदेश एक आगे बढ़ते हुए प्रदेश की श्रेणी में पहुंचा है।

विजया पाठक

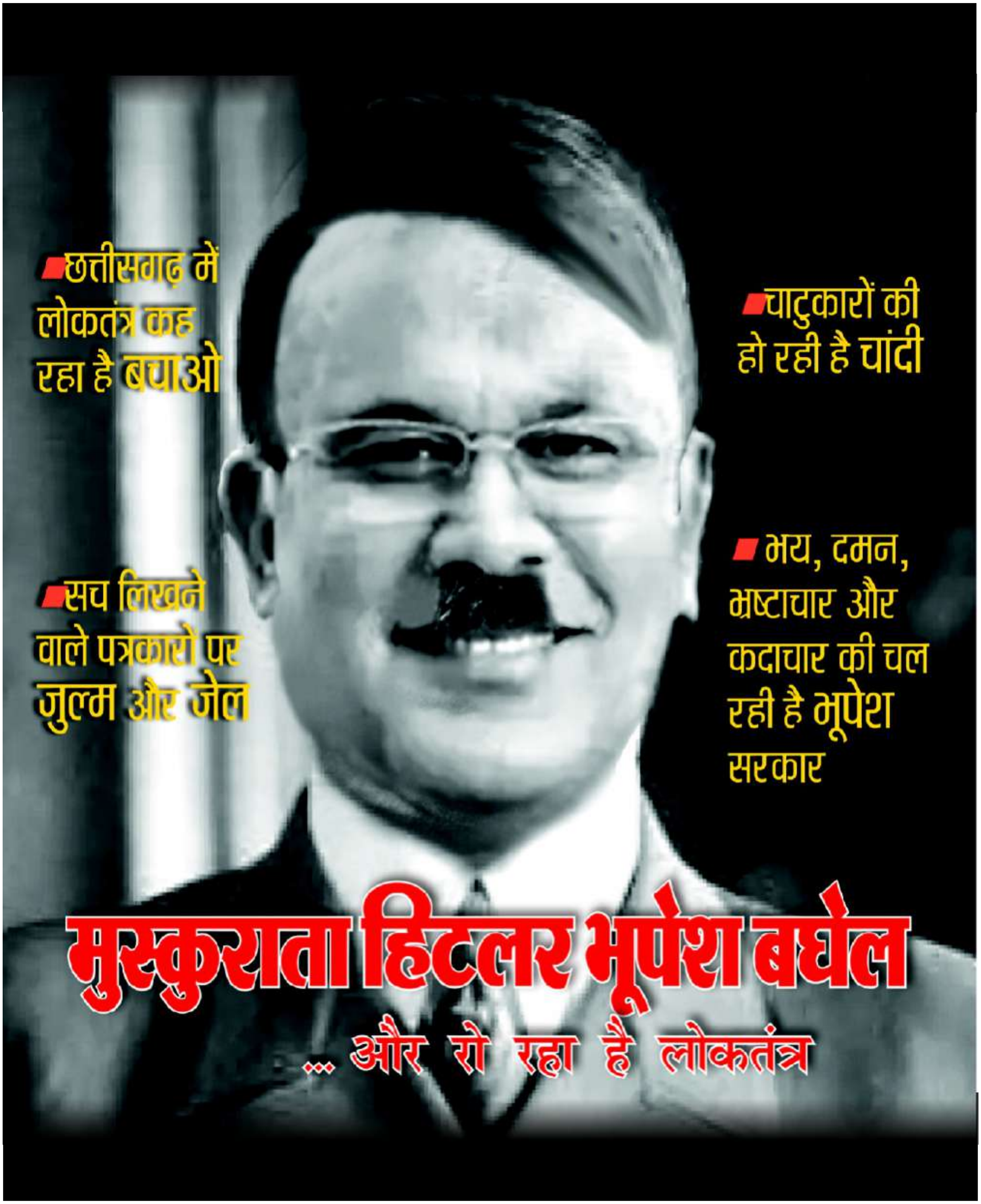
छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र कह रहा है बचाओ
सच लिखने वाले पत्रकारों पर जुल्म और जेल
चाटुकारों की हो रही है चांदी
भय, दमन, भ्रष्टाचार और कदाचार की चल रही है भूपेश सरकार
मुस्कुराता हिटलर भूपेश बघेल
... और रो रहा है लोकतंत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिटलर शाही के सामने हिटलर भी कमतर लगते हैं। प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर आपके मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट चांडाल चौकड़ी ने दमन किया है। वैसा तो हिटलर के शासन में भी नहीं देखा जाता था। हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य में घोषित आपातकाल लगाया था, निश्चित तौर पर आजाद भारत के पहले घोषित तानाशाह के रूप में भूपेश बघेल जरूर जाने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तानाशाही का व्यवहार भूपेश बघेल के लिए आम बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो प्रदेश में लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। एक उदाहरण तो मैं ही हूँ, मेरे भोपाल आवास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पुलिस भेजकर मुझे डराना चाहा था। अवैध तरीके से डिटेंशन की कोशिश की गई। पत्रकार सुनील नामदेव को इनके खिलाफ लिखने के कारण जेल जाना पड़ा। उनका घर तक तोड़ दिया गया। इस तरह की छत्तीसगढ़ सरकार की ज्यादतियां भूपेश सरकार के लिए आम सी बात है, जो भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और इनके भ्रष्ट चांडाल चौकड़ी के भय-भ्रष्टाचार-दमन के खिलाफ लिखते या आवाज उठाते हैं उन पर असंवैधानिक पुलिसिया कार्यवाही हो जाती है। राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने के बाद भी इनके कारनामें उजागर करने वाले पत्रकार असुरक्षित हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में वायरल हुये व्हाट्सअप चैट से लगता है कि क्या जिला अदालतों के माननीय जज राज्य सरकार के कहने अनुसार काम करते है? प्रदेश के आईपीएस अफसर आरिफ शेख और आईएएस अनिल कुमार टुटेजा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चौकड़ी के सदस्य है, उनकी व्हाट्सएप चैटों में अदालती फैसलों पर हस्तक्षेप करने की बात उजागर होती है। वैसे इस मामले को सर्वोच्च अदालत को भी संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे छत्तीसगढ़ की न्याय पालिका में सरकार कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। भय और दमन से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई जा रही है, कोई इनकी कारगुजारिया उजागर करता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता और सजा को लेकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके मंत्री लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहे है। राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद राजनीति नये मोड़ पर है। सीएम बघेल के खास करीबी और प्रिय उपसचिव सौम्या चौरसिया की बिलासपुर हाईकोर्ट से लंबित जमानत याचिका को लेकर सीएम बघेल खासे परेशान बताये जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान समय में मुश्किल में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का, सट्टा का, नशा का, अपराध का गढ़ बन चुका है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, आईएएस अधिकारी कोयला माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, आनलाईन गेमिंग जैसे सट्टे माफिया के रूप में संलिप्त हैं। दुबई से संचालित महादेव एप में सट्टा चल रहा है। प्रदेश में अवैध शराब कार्टल पर भी ईडी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में कोयला से वसूली का रैकेट ईडी ने पर्दाफाश किया। इसमें आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता सामने आयी है। जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के अवैध गठजोड़ से स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। शराब में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार की भी जांच भारत सरकार कोयले की तर्ज पर कर रहा है और फिलहाल अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत प्रदेश की शराब लाबी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब ईडी के ताजा छापे इसी कड़ी को जोड़कर देखा जाए। भष्टाचार में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संलिप्त हैं। आये दिन भ्रष्टाचार के उजागर होते मामलों ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। भूपेश सरकार भ्रष्टाचार करने में चरम पर पहुंच चुकी है। ईडी, आईटी और आयकर विभाग की हर दिन हो रही कार्यवाहियों से यही लगता है कि पिछले साढ़े चार साल में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। राज्य में ईडी के चौतरफा छापों से हड़कंप है। एक दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी कारोबारी ठेकेदार और माफिया ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें से चौंकाने वाले संदेही और कारोबारी अफसर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पाये गये हैं। ईडी ने ऐसे अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर घोटाले से जुडे कई दस्तावेज और हिसाब-किताब के डिजीटल साक्ष्य भी जप्त किये हैं। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर एजेंसियों का शिकंजा लगतार कंसता जा रहा है। कोल परिवहन घोटाले की फेहरिस्त में अब तक जितने आरोपी और संदेही सामने आये हैं उनका सीधा नाता सीएम बघेल और उनके परिजनों एवं नाते-रिश्तेदारों के साथ पाया गया है। बताते हैं कि ईडी ने कोर्ट में भी इस संबंध में कई डिजीटल साक्ष्य पेश किये हैं। ये साक्ष्य इन दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। नौकरशाहों और ईडी एवं सीबीआई आरोपियों के साथ आपराधिक कृत्यों से जुड़ी कई चैट सामने आने के बाद प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं की विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह पहला मौका है जब सत्ताधारी दल के नेताओं और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने खुलेआम घोटालों की झड़ी लगा दी हो। इसके बावजूद भी सरकार और उसकी वैधानिक एजेंसियों हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। प्रदेश के आला अफसरों के घर से अवैध संपत्तियों के कागजात मिल रहे हैं। इन अफसरों को भ्रष्टाचार करने की शह प्रदेश के मुखिया ने ही दी है। इसके अलावा स्वयं मुख्यमंत्री भी कई मामलों में जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। उनके वफादार अधिकारी पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं या तो जेल जाने के मुहाने पर हैं। ईडी की इतनी सख्ती के बाद भी अवैध टैक्स लेना अब भी चालू है जिसे कंपनी के माध्यम से लिया जा रहा है। यह भी सच है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। यह सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। इस जांच से यह साबित होता है कि इसमें मुख्यमंत्री पूरी तरह से संलिप्त हैं और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

विजया पाठक

वर्तमान में छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरपरस्ती में फला-फूला भ्रष्टाचार अब चरम पर पहुंच गया है। जिसकी परते भी खुलने लगी है। हर दिन हो रहे खुलासों से बघेल सरकार सकते में हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिनके हाथ में राज्य की सत्ता सौंपी, वही आज प्रदेश को लूट रह हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दिनोंदिन नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। कुछ चुनिंदा नेताओं की जुबान पर छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं अब कांग्रेस मुख्यालय में भी सुनाई देने लगी हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में सर्वमान्य आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। यह जरुर है कि राज्य में

छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले २२ वर्षो के इतिहास में यह पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के बीच टकराव देखने को मिला हो। सीएम और अध्यक्ष के बीच वाद-विवाद की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने फौरन मुददा लपक लिया था। भ्रष्टाचार के मुददे को लेकर कांग्रेस के भीतर फूट के आसार नजर आने के बाद बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में ही कांग्रेस की फजीहत कर डाली थी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी फजीहत हुई। भूपेश बघेल को विधानसभा अध्यक्ष के पैर तक पकड़ने पड़े। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।

भूपेश की अनदेखी के कारण कहीं सरकारी गवाह न बन जाये सौम्या चौरसिया

छत्तीसगढ़ में लूटमार और आतंक का पर्याय बन चुकी सुपर सीएम सौम्या चौरसिया की जमानत का मामला भी सुर्खियों में है। बताते हैं कि हाईकोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पहला झटका सीएम बघेल को ही लगा है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने सौम्या की जमानत याचिका सुनने से ठुकरा दी। हालांकि अदालत ने याचिका न सुनने का कोई ठोस कारण नही बताया है। इस मामले को लेकर अदालत का गलियारा भी गरमाया हुआ है। हाईकोर्ट के सूत्रों के मुताबिक कई जज अनिल टुटेजा और सूर्यकांत त्रिपाठी के संपर्क में थे। अब ऐसे जज और न्यायिक अधिकारियों के कामकाज का खुलासा आईपीएस आरिफ शेख और अनिल कुमार टुटेजा की मोबाईल चैट से हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया में अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा की कई ऐसी चैट वायरल हो रही हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं की कार्यप्रणालियों पर सवालिया निशान लगाती हैं। ये चैट कई आपराधिक षड़यंत्रों का भी खुलासा कर रही हैं। बताते हैं कि इस चैट में एसएसपी शेख आरिफ समेत दर्जनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का वो काला चिट्ठा सामने आया है, जो ईडी और सीबीआई के आरोपियों से जुड़ा है।

सौम्या चौरसिया वर्तमान में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। यह वही सौम्या चौरसिया है जिसको सुपर सीएम तक कहा जाता था। समय था जब इसका सिक्का सीएम हाऊस से लेकर सीएम सचिवालय तक चलता था। कहते हैं कि सौम्या के बगैर सीएम बघेल खुद कुछ फैसला नही ले पाते थे। कैबिनेट जैसी बैठक में वह सीएम को चुप करा देती थी। सौम्या का दूसरा रूप यह था कि वह प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक को क्षेत्र, जिलों में काम नही करने देती थी। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली करवाती थी। खासकर उन जिलों में या विधानसभा क्षेत्रों में जहां बीजेपी के सांसद, विधायक होते हैं या जिनमें सरकार के वह मंत्री भी शामिल हैं। जिनकी सरकार से बनती नही है। ऐसे मंत्रियों, विधायकों के क्षेत्रों में विकास के काम लगभग ठप्प करा दिये थे और होते भी थे तो उसमें कमीशनखोरी खूब होती थी। जिससे काफी अधिकारी परेशान रहते थे। यही कारण है कि सौम्या की गिरफ्तारी से सरकार के कई मंत्री, विधायक खुश हैं और सीएम बघेल भी चाहते हैं कि सौम्या जेल से बाहर ही न आये। निश्चित ही सौम्या के कारण कांग्रेस को आगामी 2023 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश की जनता ने सौम्या का दागदार चेहरा देख लिया है। सौम्या ही वही महिला अधिकारी थी जिसने जिलों या क्षेत्रों में अधिकारियों के हाथ बांध रखे थे। हो सकता है कि अब भूपेश बघेल की सौम्या चौरसिया के मामले में अनदेखी करने के कारण सौम्या सरकारी गवाह बन जाये।

आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में अपनी तैयारी जोर-शोर से कर रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अबकी बार कांग्रेस किसानों का वोट पाने के लिए नये नुस्के अपनाने की फिराक में है। कांग्रेस के रणनीतिकार बघेल के नेतृत्व में

संदीप सिंह और अर्चना गौतम के मामले में बुरे फंसे भूपेश बघेल

सीएम बघेल की खासमखास अर्चना गौतम की राजनीति में आमद मुख्यमंत्री बघेल के लिए मुश्किलों का पहाड़ बनकर टूटी है। सूत्रों के अनुसार सीएम बघेल के इशारों पर ही अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ आग उगली थी। अर्चना गौतम ने रायपुर में संदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाये थे। बताते हैं कि अर्चना गौतम की अदाकारी में भूपेश बघेल का हाथ सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बघेल की रणनीति से कांग्रेस आलाकमान वाकिफ हो गया है। सूत्रों का दावा है कि राज्य में पंजाब जैसे हालात का सामना आने वाले दिनों में कांग्रेस को करना पड़ सकता है। लिहाजा बघेल के चलते पार्टी को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए प्रियंका गांधी के रणनीतिकारों ने आदिवासी सीएम का कार्ड खेला है। कांग्रेसी खेमों से ही जानकारी आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 विधानसभा चुनाव कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसके लिए आदिवासी नेता मोहन मरकाम को सरकार की बागडोर सौंपे जाने की खबरें भी कांग्रेस के भीतरखानों से सामने आ रही हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक संदीप सिंह और बघेल के बीच तनातनी की खबरें उस समय से ही सामने आने लगी थी जब बघेल ने जोर देते हुए उत्तरप्रदेश की हस्तिनापुर जिस सीट से अर्चना गौतम को कांग्रेस की टिकिट दिलवायी थी। बताते हैं कि अर्चना गौतम को इलाके में कोई जानता पहचानता तक नहीं था। उनकी शोहरत सिर्फ मुंबई तक सीमित थी। ऐसे समय बघेल ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए अर्चना की जीत का भरोसा जताया था। बताया जाता है कि अर्चना गौतम की जीत के लिए बघेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने प्रियंका गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां करवायी। बघेल उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खुद स्टार प्रचारक थे। उन्होंने अर्चना गौतम की जीत के लिए काफी रकम पानी की तरह बहाया था। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आये तो राज्य से कांग्रेस का ही डिब्बा गायब हो गया था। कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक चुनाव जीतकर आए वो भी आपनी पारंपरिक सीट पर। आश्चर्यजनक बात यह रही थी जिस अर्चना की जीत के लिए बघेल ने कांग्रेस के सारे

ही विधानसभा चुनाव कराये जाने की जोर आजमाईश में जुटे हैं। जबकि जनता की नब्ज टटोलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी से अपना हक जताने लगे हैं। ओबीसी और साफ छवि का दावा कर

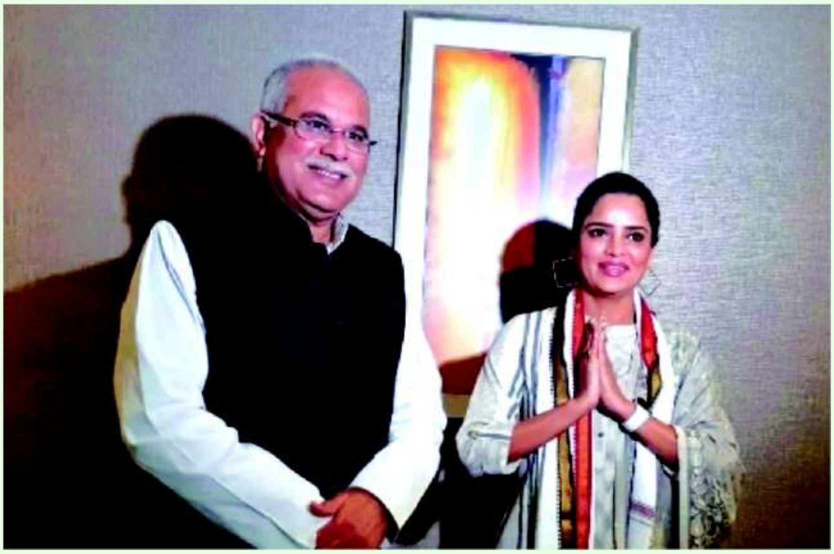

यही है भूपेश बघेल की खास अर्चना गौतम। जिसके राजनीतिक करियर बनाने के लिए भूपेश बघेल ने ऐड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब संदीप सिंह और अर्चना गौतम के नये मामले में बघेल बुरे फंसे नज़र आ रहे हैं।

संसाधन झोंक दिये थे। अर्चना गौतम की जमानत तक जप्त हो गई थी। फिलहाल अर्चना गौतम और संदीप सिंह के बीच का विवाद बघेल की गले की फांस बन गया है। दरअसल इस विवाद को लेकर अर्चना के पिता ने उत्तरप्रदेश के हस्तिनापुर के एक थाने में संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में अर्चना को जातिगत गाली गलौच और उनकी जान को खतरा होने का हवाला दिया गया था। बताते हैं कि इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद मामला छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। चूंकि विवाद का स्थल रायपुर है। इसलिए आगे की विवेचना छत्तीसगढ़ पुलिस को करनी है और छत्तीसगढ़ पुलिस भूपेश बघेल के अधीन है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि संदीप सिंह को घुटने पर टेकने पर मजबूर करने के लिए बघेल ने अर्चना के कंधों पर बंदूक रखकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला था। उनका मानना है कि अपने गृहनगर हस्तिनापुर में संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर अर्चना गौतम ने नहीं बल्कि उनके पिता ने दर्ज कराई थी। जबकि यह सर्वविदित है कि रायपुर में फेसबुक लाईव कर होटल से ही सोशल मीडिया में अर्चना गौतम ने संदीप सिंह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। अर्चना गौतम ने ललकारते हुए संदीप को कई चुनौतियां भी दी थी। बावजूद इसके खुद अर्चना गौतम ने रायपुर में संदीप सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई बल्कि इस मामले को अपने गृहनगर हस्तिनापुर पहुंचाया। यहां अपने पिता के मार्फत एफआईआर दर्ज करवाकर उसे आगे की कार्यवाही के लिए रायपुर स्थानांतरित करवाया गया। बताते हैं कि अर्चना गौतम तो सिर्फ मोहरा है। बहरहाल अर्चना गौतम को बघेल इंसाफ दिलवा पायेंगे या फिर संदीप सिंह की बेगुनाही के लिए अर्चना गौतम के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने का मुकदमा दर्ज करवायेंगे यह देखना गौरतलब होगा। वैसे इस मामले में अगर कांग्रेस जांच कराए कि छत्तीसगढ़ का कौन बड़ा नेता दिल्ली से छत्तीसगढ़ भवन से निकलकर अर्चना गौतम से मिलने जाते थे, इसकी मालूमात करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

गृहमंत्री ताम्रकार साहू पहले से ही मुख्यमंत्री के दावेदार बताये जाते हैं। बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री पद पर चुनौती पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की सूरत में मोहन

छत्तीसगढ़ : विधायिका और कार्यपालिका में रार

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले विधानसभा के हंगामेदार नजारों से कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। आदिवासी इलाका हो या फिर मैदानी, कांग्रेस के ही विधायकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये विधायक सरकारी संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार से दो-चार हो रहे हैं। अबकी बार उन्हें अपनी विधायकी खतरे में नजर आने लगी है। लिहाजा कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर बाहर भूपेश बघेल की घेराबंदी कर अपने इरादे साफ कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामे की शुरूआत उस समय हुई जब राज्यपाल ने अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन में अपना मुंह मोड़ लिया था। बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में आग उगलने वाले विधायकों को अधिक से अधिक बोलने का मौका देने से चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तीखी नोंकझोंक हो गई थी। सूत्र बताते है कि दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि महंत का न्याय का पक्ष लेते हुए सदन से विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देने की पेशकश कर दी थी। बताते हैं कि लगातार दो दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सदन की कार्यवाही से नदारद रहे थे। सीएम और अध्यक्ष के बीच वाद-विवाद की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने फौरन मुददा लपक लिया था। भ्रष्टाचार के मुददे को लेकर कांग्रेस के भीतर फूट के आसार नजर आने के बाद बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में ही कांग्रेस की फजीहत कर डाली थी। बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बघेल के रूख पर हैरानी जताई। उन्होंने संसदीय परंपराओं का अपमान बताते हुए सीएम बघेल से इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। बताते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद मुश्किल में पड़े बघेल ने चरणदास महंत के चरण पकड़ लिये थे। सदन में कांग्रेस और सरकार की फजीहत का हवाला दिये जाने के बाद ही महंत ने बघेल के अनुरोध को स्वीकार कर सदन में अपने पांव रखे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले 22 वर्षो के इतिहास में यह पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के बीच टकराव देखने को मिला हो। बताते हैं कि बीजेपी के मुखर होते ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो निशान जिसके चलते आम जनता के बीच सीएम बघेल की छवि किसी लुटेरे से कम नहीं आंकी जा रही है।

मरकाम, चरणदास महंत और ताम्रकार साहू के बीच मुकाबले के आसार बढ़ गए हैं। जानकार बताते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर भूपेश बघेल के दिन लगभग समाप्ति की ओर हैं। ऐसे में माना जा रहा

निगम मण्डल आयोग की नियुक्तियों में विसंगति

अटल श्रीवास्तव को प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के विरोध के बाद भी 2019 में बिलासपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जो लगभग पौने दो लाख मतों से चुनाव हार गए, बावजूद उन्हें पर्यटन मण्डल का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अटल श्रीवास्तव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुराने मित्र रहे हैं। 2018 में बिलासपुर से विधानसभा चुनाव की तैयारी में थे, पर उस समय के भारी विरोध के कारण इनको टिकिट नहीं दिया गया।

छत्तीसगढ़ में 2360 सेवा सहकारी समिति हैं। इन समितियों में अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए गिरीश देवांगन एवं विनोद वर्मा को अधिकृत कर दिया गया, विधायकों ने बगैर संगठन के जिला इकाई व ब्लॉक कॉंग्रेस से बात किये अपने अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिये। विधानसभा क्षेत्र-19 विधानसभा में गिरीश देवांगन ने अपने हिसाब से नियुक्ति कर दी जिसका पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में विरोध है।

धनुष सेन वह व्यक्ति है जो कि गाँजा तस्करी के आरोप में जेल में थे, पार्टी ने छः साल के लिए निष्काषित भी किया था। इन्हें केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया।

रामकुमार पटेल अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में न्यायालय से 7 वर्ष की सजा का दोषी अपराधी है। कांग्रेस के रामकुमार पटेल को शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि गत 7 वर्ष जेल की सजा काटकर निकले थे।

विपिन्न साहू जो कि वर्ष 2017 में भाजपा छोड़ कॉंग्रेस में आये, उन्हें 2018 में छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

संदीप साहू जो कि 2019 में जोगी कॉंग्रेस छोड़कर कॉंग्रेस में आये और इन्हें तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया।

है कि कांग्रेस किसी नये चेहरे पर मुख्यमंत्री पद की मोहर लगा सकती है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरु हो गई हैं। बीजेपी और उसके नेता चुनावी मैदान में कूद गए हैं। पार्टी के केन्द्रीय

चैटिंग से खुल रहीं भ्रष्टाचार की परतें

क्या आरिफ शेख आईपीएस (छग) होंगे सेवा से बर्खास्त?

छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात प्रदेश के कई आईपीएस, आईएएस एवं अन्य अधिकारियों ने राजनैतिक शरण के लिए सत्ता के आगे नतमस्तक करने का चलन चालू हुआ। साल दर साल अधिकारियों की राजनैतिक सांठगांठ बढ़ती ही गई जोकि 2018 के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही अपने चरम पर पहुंच गई। पूर्ववर्ती सरकार में ऐसे उदाहरण दिखते हैं जैसे राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्ष निलंबित रहे। पर 2018 में कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान अधिकारियों ने स्थापित कर दिये। मलाईदार पोस्टिंग और मुख्यमंत्री की कोठरी में आने के लिए इन अधिकारियों ने तमाम हथकंडे अजमाये इसका एक उदाहरण प्रदेश के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख रहें हैं। आरिफ शेख को कांग्रेस सरकार बनते ही राजधानी रायपुर में पदस्थ किया गया। इसके बाद इनकी पात्रता नहीं होने के बावजूद इनको डिप्टी आई जी एन्टीकरप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं आर्थिक प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू में पदस्थ कर दिया गया। इन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुये मुख्यमंत्री और उनकी चांडाल चौकड़ी के खिलाफ जिसने भी लिखने और बोलने की हिम्मत की उनके उपर पुलिसिया दबाव और साजिशें की। इसका खुलासा तब हुआ जब इनकी व्हाटसअप चैट मीडिया में वायरल हुई, जिसमें यह अनिल कुमार टुटेजा ऊर्फ AKT ऊर्फ TA Kumar से अपने कार्य और कार्यालय संबंधी बातें करते दिखे। यश टुटेजा ऊर्फ YT जोकि अनिल कुमार टुटेजा के पुत्र है उनसे भी चैट करते थे। आरिफ शेख अनिल कुमार टुटेजा से न केवल चैटिंग करते थे बल्कि उस चैटिंग में वह उनसे अवैध आदेश भी प्राप्त करते थे। इन

R.N.I. No. M.P.E.B.I.L./2001/5256
DAVP Code : 128101
जगत VISION
मासिक द्विभाषी पत्रिका
क्रमांक : 2023/23
दिनांक : 21/03/23

आईपीएस आरिफ शेख के असंवैधानिक कृत्यों की शिकायत जगत विजन द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ शासन को की गई।

संगठन ने नये नेताओं को तरजीह देकर संगठन में जान फूंक दी है। हालांकि पार्टी के भीतर वो नेता चुनौती लेकर उभर रहे हैं, जो 15 सालों तक सत्ता की मलाई खाकर तंदुरुस्त हो गए थे। ऐसे नेताओं का साथ और भूपेश बघेल का हाथ उनके

चैटिंग से खुल रहीं भ्रष्टाचार की परतें

चैटों में रिंकू खनूजा केस का उल्लेख किया गया है। गौर करने वाली बात है कि रिंकु खनूजा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विनोद वर्मा, राजेश मूणत अश्लील सीडी काण्ड के आरोपी हैं। इसमें से रिंकू खनूजा ने बाद में आत्महत्या कर ली जिसके बाद से इस केस के तमाम गवाहों को डरा धमका कर होस्टाईल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर के लिए याचिका भी लगाई है। इन चैटों को आयकर विभाग ने तीस हजारी कोर्ट के सामने रखा है। यह चैट केन्द्रीय एजेंसी द्वारा यश टुटेजा और अनिल टुटेजा पर छापेमारी के बाद उनके मोबाईल नम्बर से निकाले गये थे। खासबात यह है कि अनिल कुमार टुटेजा खुद मुख्यमंत्री की चाण्डाल चौकड़ी के महत्वपूर्ण सदस्य है और इस समय 36 हजार करोड़ के नान घोटाले के मुख्य अभियुक्त है। ऐसे में आरिफ शेख अनिल कुमार टुटेजा से किस हैसियत से अपने रोजमर्रा शासकीय कार्य की चर्चा करते थे एवं उनसे आदेश लेते थे जबकि अनिल कुमार टुटेजा न तो गृह विभाग या उससे संबंधित किसी विभाग में पोस्टिंग पर नहीं थे। आरिफ शेख ने केवल अनिल कुमार टुटेजा बल्कि उनके पुत्र यश टुटेजा उर्फ YT से भी अपने कार्य संबंधी चैटिंग किया करते थे जबकि यश टुटेजा रायपुर शहर के एक छोटे-मोटे व्यवसायी हैं जिन पर आयकर विभाग के छापे भी पड़े थे। इन चैटिंग में यश टुटेजा द्वारा मुंबई से लाये हुये कोई उपहार का भी उल्लेख है जिसे आरिफ शेख ने धन्यवाद लिखकर स्थापित भी किया था। आरिफ शेख द्वारा अपने पद का प्रभाव दिखलाते हुये इस चाण्डाल चौकड़ी के कुकर्मो पर पर्दा डालने के कोशिश करते थे, चाहे अपने वरिष्ठ अधिकारी को फंसाने की बात हो, पत्रकारों के खिलाफ षडयंत्र रचना, मुख्यमंत्री और अनिल टुटेजा के केस संबंधी गवाहों को होस्टाईल करने की कोशिश हो या राज्य ज्यूडिशियरी पर प्रेशर डालने की बात सारे अनैतिक काम आरिफ शेख (आईपीएस 2005 बैच) ने किया। आरिफ शेख ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कंडिका 12, 14 का उल्लंघन किया। इसके साथ ही इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1968 की कंडिका 3(2बी)ए (6,12), कंडिका 8, कंडिका 9, कंडिका 11 का उल्लंघन किया एवं भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 का उल्लंघन किया है। जिससे आगे जाकर इस मामले में इनकी सेवा बर्खास्तगी हो सकती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमन सिंह मामले में एक नजीर पेश की, जिसमें उन्हें बिलासपुर हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद वापस दोषी ठहरा दिया है। विडंबना है कि प्रदेश के ऐसे युवा आईपीएस किस कदर भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंस कर अपनी सेवा बर्खास्तगी की नौबत तक आ पहुंचे हैं। आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में कुख्यात हो गया है।

साथ नज़र आने से शीर्ष आलाकमान अलर्ट मोड पर है। उसने इसका ईलाज भी शुरू कर दिया है। लिहाजा माना जा रहा है कि पूरे दम के साथ चुनावी मैदान में डटी नजर आयेगी। उधर सत्ता के मद में डूबी मुख्यमंत्री बघेल की सरकार लगातार

पूर्व ओएसडी रवि पटनायक के मोबाईल डाटा पर छत्तीसगढ़ पुलिस की निगाहें

मोबाईल डाटा से कई राज खुलने की आशंका

छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन आईपीएस अधिकारियों के काले कारनामें उजागर हो रहे हैं। खाकी वर्दी की आड़ में राज्य के पुलिस अधिकारी रोजाना नए-नए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली से न केवल पीड़ितों के परिजनों पर गैरकानूनी कार्यो के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि सरकारी तंत्र अपनी गैर जिम्मेदारी वाली कार्यशैली से अदालतों को भी प्रभावित कर रहा है। सरकारी मशीनरी के जरिये आपराधिक तत्व अदालतों से मनचाहा फरमान जारी करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ताजा मामला पूर्व ओएसडी रवि पटनायक के खिलाफ दर्ज फर्जी एफआईआर और उसे अधिकतम दिनों तक जेल में निरुद्ध रखने से जुड़ा है। रवि पटनायक को मनी लांड्रिंग से जुड़े कई असली मामले में ईडी पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लेती उससे पहले पटनायक को राज्य स्तरीय एजेंसी ने धर दबोचा है। रवि पटनायक ईडी के सामने अपना मुँह खोलता, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है।

रवि पटनायक पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार में कई मंत्रियों का ओएसडी रह चुका है। एक आईपीएस अधिकारी के निर्देश पर उसका फर्जी आई कार्ड बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरोकार रखने वाले किसी भी मामले के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस अधिकारी सबसे पहले उस शख्स का मोबाईल अपने कब्जे में लेने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं। इसके लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि चढाने में भी परहेज नहीं करते। अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया का प्रमुख राजदार रवि पटनायक और उसका परिवार इन दिनों सरकारी जुल्मो सितम का शिकार हो रहा है। राज्य के पुलिस अफसर रवि पटनायक के मोबाईल की जप्ती को लेकर जमकर हाथ पैर मार रहे हैं। इसके लिए न्यायपालिका का भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

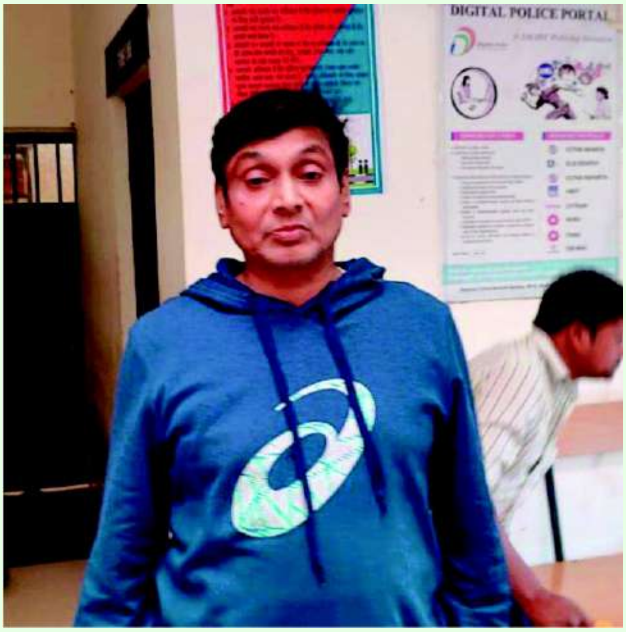

पिछले लगभग तीन माह से रवि पटनायक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब रवि पटनायक की गिरफ्तारी के बाद से अखिल भारतीय सेवाओं के कई अधिकारियों की सांसे फूली हुई हैं। ऐसे कुछ अफसर पटनायक के मोबाईल फ़ोन की जप्ती को लेकर बेचैन हैं। मोबाईल हाथ लगते ही उसके डाटा डिलीट करने को लेकर जूनियर आईपीएस अधिकारियों ने अपनी कमर कसी हुई है। इसके लिए विधि सचिव राम कुमार तिवारी और अनिल टुटेजा रायपुर जिला अदालत में पदस्थ कतिपय ऐसे जजों के संपर्क में है, जो छत्तीसगढ़

दूसरी बार बाजी मारने के लिए अपना अंजाम देने में जुटी है। इसके लिए उसने अपनी चुनावी टीम में उन आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया है जो गैर कानूनी गतिविधियों में भी खुलकर मुख्यमंत्री बघेल के साथ खड़े

गिरोह के लिए न्याय का सौदा करते हैं। सूत्रों का कहना है कि रवि पटनायक के मोबाईल में अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के गुनाहों के सबूतों के अलावा उनके सरदार भूपेश बघेल के काले कारनामों का डिजिटल डाटा मौजूद है। सूत्र बताते हैं कि रवि पटनायक मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ सौम्या चौरसिया के साथ कई बड़ी डीलिंग में शामिल था। उसने अपने आकाओं के लिए कई बड़े आर्थिक सौदों को अंजाम तक पहुंचाया था। सौम्या चौरसिया के ईडी के हत्थे चढ़ते ही रवि पटनायक गायब हो गया था। सूत्रों के अनुसार पूर्व में रायपुर रेंज में और मौजूदा महासमुंद पदस्थ आईजी शेख आरिफ और दुर्ग रेंज में कार्यरत आईजी आनंद छाबड़ा के मार्गदर्शन में रवि पटनायक को रायपुर सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया है। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद से ईडी की निगाहें रवि पटनायक पर टिकी हुई थी। ईडी कुछ महत्वपूर्ण सौदों और उससे जुडी वसूली को लेकर रवि पटनायक से पूछताछ के प्रयास में जुटी हुई थी। इसकी भनक लगते ही शेख आरिफ के प्लान के मुताबिक पुलिस ने रवि पटनायक के खिलाफ एक फर्जी प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने रवि पटनायक के खिलाफ नया रायपुर के राखी थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी किसी केंद्रीय एजेंसी से उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता बताई जा रही है।

अनिल टुटेजा और रवि पटनायक के बीच आखिरी मुलाकात के बाद रातों रात उसे कब्जे में लेने की कवायत शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ भी फर्जी प्रकरण दर्ज करने के लिए पहले शिकायतकर्ता, गवाह और जज का प्रबंध किया गया था। अदालती कार्यवाही के तहत रवि पटनायक को जेल दाखिल कराने के बाद अब उसके मोबाईल की जप्ती के प्रयास किये जा रहे हैं। साजिश के सामने आने के बाद जेल में बंद रवि पटनायक पर अपना मोबाईल जप्त करवाए जाने को लेकर पुलिस का दबाव बढ़ गया है। कई अफसरों की मुश्किल इन दिनों ईडी ने बढ़ा दी हैं। पुलिस की आधी–अधूरी आपराधिक दास्तान सामने आने के बाद ईडी भी रवि पटनायक के मोबाईल फोन और अन्य डिजीटल उपकरणों की वैधानिक जप्ती को लेकर सक्रिय है। रवि पटनायक के मोबाईल फ़ोन की जप्ती से जुड़े कुछ एक साजिशकर्ताओं की चर्चित कार्यप्रणाली पर ईडी की पैनी निगाहें बताई जाती हैं। सूत्र बताते हैं कि रवि पटनायक की जमानत के लिए सौदेबाजी का दौर जारी है। बताते हैं कि एक हाथ मोबाईल दो दूसरे हाथ जमानत लो के ऑफर से पीड़ित परिवार पसोपेश में है। परिवार ने ईडी को अपनी आपबीती सुनाई है। रवि पटनायक मामले को लेकर जाँच एजेंसियां दस्तावेजी प्रमाणों के साथ कुछ एक अफसरों पर अपना शिकंजा कस सकती है।

रहे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अबकी बार भूपेश कांग्रेस पर निर्भर नही हैं। कांग्रेस का संचालन उन पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री बघेल के मौजूदा साढ़े चार सालों में जो अर्जित किया है उसके दमखम पर वो बीजेपी को बौना साबित

भूपेश बघेल और उनकी चांडाल चौकड़ी पर भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के छापे पड़ रहे हैं

छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड का महौल फिर से गरम हो गया है, इस बार के. के. श्रीवास्तव (भूपेश बघेल के लिए दतिया से लाकर पंडितों से पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति) कोयला ट्रांसपोर्ट व्यवसाई, जनसंपर्क व परिवहन में नियुक्त आईपीएस दीपांशु काबरा, IAS अधिकारी के. डी. कुंजाम के साथ साथ रामगोपाल अग्रवाल के रिश्तेदार, महासमुन्द के विधायक चंद्राकर और कमल सारदा (प्रमुख व्यवसायी), रायगढ़ में रतेरिया और अशोक सिंघल के यहां ईडी द्वारा कार्यवाही की गई थी। इसके अलावा शराब कार्टल मामले अनिल टुटेजा, प्रदेश के समस्त व्यवसायी, अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल को ईडी ने नोटिस देकर पूछताछ की है और इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी कुछ 125 से ऊपर की छापेमारिया ईडी छत्तीसगढ़ में कर चुकी है। वहीं भूपेश बघेल कहते नहीं थक रहे की प्रदेश में फिर ईडी आई है। भूपेश बघेल जो भय–भ्रष्टाचार–कदाचार वाली पिछले चार साल से जो सरकार चलाई है उसका नतीजा अब निकल के आ रहा है। आपके इस भ्रष्टाचार के महाखेला के चक्कर में प्रवेश कैडर के कम से कम 10 आईएएस–आईपीएस अधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी निश्चित है। कोई ईडी सीबीआई 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रारंभिक जांच में यूंही नहीं पकड़ लेता है।

करने की रणनीति पर आमादा है। राजनीति के जानकार यह भी बताते हैं कि बघेल ने कई बड़े आर्थिक पैकेज तैयार किये हैं। इसके जरिये वो बीजेपी के रणनीतिकारों और जमीनी नेताओं को खासा तवज्जो दे रहे हैं। जाहिर है उनकी

ईडी रेड की दूसरी चार्जशीट में हुए हैरतअंग्रेज खुलासे

दिनांक 30-01-2023 को ईडी ने अपनी दूसरी चार्जशीट विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। पीएमएलए एक्ट के अभियुक्त सौम्या चौरासिया, अनुराग चौरसिया, दीपेश टोंक, रजनीकांत तिवारी, कैलाश तिवारी, संदीप कुमार नायक, शिव शंकर नाग और राजेश चौधरी के खिलाफ यह प्रस्तुत किया गया। इस चार्जशीट में सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को मुख्य साजिश करता बताया गया। सूर्यकांत तिवारी ने अवैध कोल टैक्स कलेक्शन के लिए 8 लोगों को नौकरी पर रखा था, जिसमें निखिल चंद्राकार, रोशन कुमार सिंह, राहुल सिंह, नवनीत तिवारी, पारेख कुर्रे, मोइनुद्दीन कुरैशी, चंद्र प्रकाश जायसवाल और वीरेंद्र जायसवाल थे। इन कर्मचारियों को दबिश देने पर इनके पास से बड़ी सामग्री मिली, जिससे अवैध कोयला टैक्स के महाखेला में किसको कितना पैसा दिया गया उसके साक्ष्य मिले। इस चार्जशीट को बेहद ही सुलभ तरीके से समझाया गया कि कैसे अवैध कोल टैक्स का पूरा कार्टेल बना। इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी थे। कहने की जरूरत नहीं की परदे के पीछे के इस खेल का असली खिलाड़ी कौन था। दिनांक 15-07-2020 आईएएस समीर विश्नोई जो उस समय डायरेक्टर माइनिंग और जियोलॉजी थे उन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला जिसमे कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब तक 25 रुपए प्रति टन (अवैध कोयला टैक्स) ना पहुंचे, तब तक संबंधित व्यक्ति/कंपनी को डिस्पैच ऑर्डर ना दिए जाए। इन पैसों का कलेक्शन करके सूर्यकांत तिवारी अधिकारियों को रिश्वत, नेताओं को पैसे, चुनावी फंडिंग, विधायकों/मंत्रियों के दिल्ली प्रवास के दौरान करता, अय्याशी की सामग्री दिलवाना, बेनामी संपत्ति का अर्जन करता था। सूर्यकांत तिवारी सौम्या चौरसिया को रिपोर्ट करता था। और आगे सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट करती थी। इसके बाद पैसा का उपयोग नेताजी को देने और बेनामी प्रॉपर्टी अर्जित करने में लगाते गए, इनमे से 152.31करोड़ की संपत्ति ईडी ने दिनांक 9-12-22 को अटैच भी कर दी थी। जब्त डायरियों के

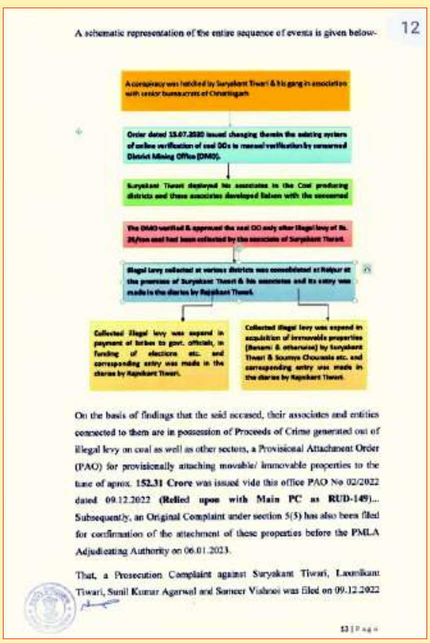

12

A schematic representation of the entire sequence of events is given below-

A conspiracy was hatched by Suryakant Tiwari & his gang in association with senior bureaucrats of Chhattisgarh

Order dated 15.07.2020 issued changing therein the existing system of online verification of coal DOs to manual verification by concerned District Mining Office (DMO).

Suryakant Tiwari deployed his associates in the Coal producing districts and these associates developed liaison with the concerned

The DMO verified & approved the coal DO only after illegal levy of Rs. 25/ton coal had been collected by the associate of Suryakant Tiwari.

Illegal levy collected at various districts was consolidated at Raipur at the premises of Suryakant Tiwari & his associates and its entry was made in the diaries by Rajnikant Tiwari.

Collected illegal levy was expend in payment of bribes to govt. officials, in funding of elections etc. and corresponding entry was made in the diaries by Rajnikant Tiwari.

Collected illegal levy was expend in acquisition of immovable properties (Benami & otherwise) by Suryakant Tiwari & Soumya Chourasia etc. and corresponding entry was made in the diaries by Rajnikant Tiwari.

On the basis of findings that the said accused, their associates and entities connected to them are in possession of Proceeds of Crime generated out of illegal levy on coal as well as other sectors, a Provisional Attachment Order (PAO) for provisionally attaching movable/ immovable properties to the tune of aprox. **152.31 Crore** was issued vide this office PAO No 02/2022 dated 09.12.2022 **(Relied upon with Main PC as RUD-149)**.. Subsequently, an Original Complaint under section 5(5) has also been filed for confirmation of the attachment of these properties before the PMLA Adjudicating Authority on 06.01.2023.

That, a Prosecution Complaint against Suryakant Tiwari, Laxmikant Tiwari, Sunil Kumar Agarwal and Sameer Vishnoi was filed on 09.12.2022

13 | Page

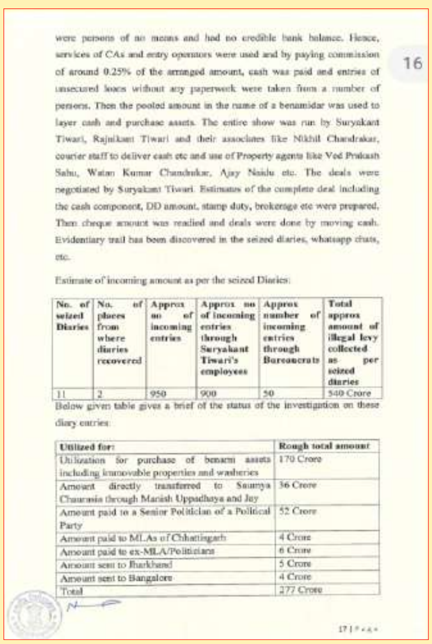

16

were persons of no means and had no credible bank balance. Hence, services of CAs and entry operators were used and by paying commission of around 0.25% of the arranged amount, cash was paid and entries of unsecured loans without any paperwork were taken from a number of persons. Then the pooled amount in the name of a benamidar was used to layer cash and purchase assets. The entire show was run by Suryakant Tiwari, Rajnikant Tiwari and their associates like Nikhil Chandrakar, courier staff to deliver cash etc and use of Property agents like Ved Prakash Sahu, Watan Kumar Chandrakar, Ajay Naidu etc. The deals were negotiated by Suryakant Tiwari. Estimates of the complete deal including the cash component, DD amount, stamp duty, brokerage etc were prepared. Then cheque amount was readied and deals were done by moving cash. Evidentiary trail has been discovered in the seized diaries, whatsapp chats, etc.

Estimate of incoming amount as per the seized Diaries:

No. of seized Diaries	No. of places from where diaries recovered	Approx no of incoming entries	Approx no of incoming entries through Suryakant Tiwari's employees	Approx number of incoming entries through Bureaucrats	Total approx amount of illegal levy collected as per seized diaries
11	2	950	900	50	540 Crore

Below given table gives a brief of the status of the investigation on these diary entries:

Utilized for:	Rough total amount
Utilization for purchase of benami assets including immovable properties and washeries	170 Crore
Amount directly transferred to Saumya Chaurasia through Manish Uppadhaya and Jay	36 Crore
Amount paid to a Senior Politician of a Political Party	52 Crore
Amount paid to MLAs of Chhattisgarh	4 Crore
Amount paid to ex-MLA/Politicians	6 Crore
Amount sent to Jharkhand	5 Crore
Amount sent to Bangalore	4 Crore
Total	277 Crore

17 | Page

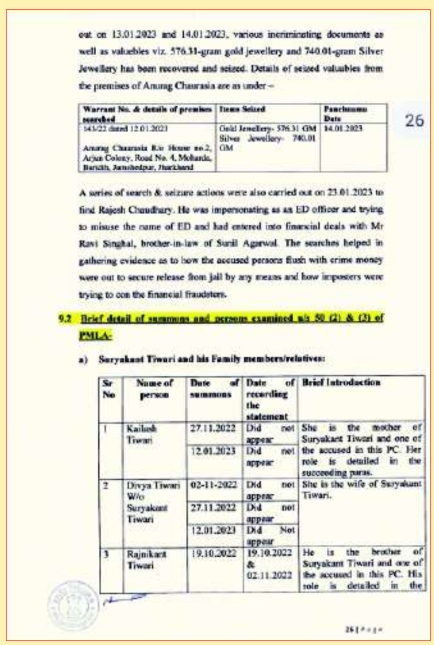

26

out on 13.01.2023 and 14.01.2023, various incriminating documents as well as valuables viz. 576.31-gram gold jewellery and 740.01-gram Silver Jewellery has been recovered and seized. Details of seized valuables from the premises of Anurag Chaurasia are as under –

Warrant No. & details of premises searched	Items Seized	Panchnama Date
143/22 dated 12.01.2023 Anurag Chaurasia R/o House no.2, Arjun Colony, Road No. 4, Moharda, Baridih, Jamshedpur, Jharkhand	Gold Jewellery- 576.31 GM Silver Jewellery- 740.01 GM	14.01.2023

A series of search & seizure actions were also carried out on 23.01.2023 to find Rajesh Chaudhary. He was impersonating as an ED officer and trying to misuse the name of ED and had entered into financial deals with Mr Ravi Singhal, brother-in-law of Sunil Agarwal. The searches helped in gathering evidence as to how the accused persons flush with crime money were out to secure release from jail by any means and how imposters were trying to con the financial fraudsters.

9.2 Brief detail of summons and persons examined u/s 50 (2) & (3) of PMLA-

a) Suryakant Tiwari and his Family members/relatives:

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
1	Kailash Tiwari	27.11.2022	Did not appear	She is the mother of Suryakant Tiwari and one of the accused in this PC. Her role is detailed in the succeeding paras.
		12.01.2023	Did not appear	
2	Divya Tiwari W/o Suryakant Tiwari	02-11-2022	Did not appear	She is the wife of Suryakant Tiwari.
		27.11.2022	Did not appear	
		12.01.2023	Did Not appear	
3	Rajnikant Tiwari	19.10.2022	19.10.2022 & 02.11.2022	He is the brother of Suryakant Tiwari and one of the accused in this PC. His role is detailed in the

26 | Page

ईडी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत अपनी दूसरी चार्जशीट में किए सनसनीखेज खुलासे, आखिर 52 करोड़ की रिश्वत किस राजनेता को दी गई।

चाल बीजेपी को उनके ही प्यादों से ठिकाने लगाने की है। हालांकि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मामलों में मुख्यमंत्री और उनका कुनबा बुरी तरह से घिर चुका है।

बघेल के पुत्र चेतन्य बघेल से ईडी

अनुसार 540 करोड़ का कोयला लेवी टैक्स वसूला गया जिसमे से 52 करोड़ कांग्रेस के बड़े नेता को दिए गए। सौम्या चौरसिया पर प्रवर्तन निदेशालय ने जो दूसरी चार्टशीट प्रस्तुत की उसमें कांग्रेस में उपरोक्त नेताओं के नाम भी थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब उनकी नजर प्रदेश के आईपीएस लॉबी के अलावा भूपेश बघेल के पुत्र का भी नाम है, पूछताछ में उनके पुत्र का नाम लिया गया है। ऐसे में कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पापों का घड़ा भरता नजर आ रहा है। ईडी द्वारा हाल ही में पेश की गई चार्जशीट में शामिल बघेल और चौरसिया के करीबियों के नाम को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया के लिए आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि बघेल और चौरसिया के जिन करीबियों के नाम ईडी ने चार्ज शीट में शामिल किये हैं उनमें कई ऐसे है जिनके पास बघेल और चौरसिया के भ्रष्टाचारों का पुलिंदा है। चार्ज शीट में ईडी ने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप सचिव सौम्या चौरसिया के करीबियों के पास मौजूद दस्तावेज बघेल और चौरसिया को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है।

ईडी द्वारा जारी की गई चार्जशीट में आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता के नाम पर 10 लाख रुपये की राशि दर्ज है। यह राशि उन्होंने कोयला दलाल सूर्यकांत तिवारी से कोयला घोटाला करने के लिए ली थी। ईडी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट में उन पत्रों का हवाला भी दिया है, जिसमे कई कांग्रेसी नेताओं को दी जाने वाली नगद रकम का हिसाब–किताब दर्ज है। एक और सनसनीखेज खुलासा इस चार्जशीट से हुआ जिसमें प्रदेश के चार आईपीएस अधिकारियों की सांठगांठ अवैध कोल टैक्स घोटाले में थी। आईपीएस अधिकारी पारुल साहू, प्रशांत अग्रवाल, भोजराम पटेल और अमित कुमार दुबे का नाम इस चार्जशीट में आया है। खास बात है पारुल माथुर का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से उप पुलिस महानिरीक्षक ACB रायपुर किया गया है। इसके पूर्व ED ने 27.11.2022 को समन जारी कर दिनांक 30.11.2022 को उनके

b) Employees of Suryakant Tiwari:

26

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
4	Mohsin Khan	16.11.2022 27.11.2022 22.12.2022 14.01.2023	Did not appear Did not appear Did not appear 19.01.2023	He is an employee of Suryakant Tiwari and used to collect & deliver the cash as per the instructions of Suryakant Tiwari.
5	Sheikh Moinuddin Qureshi	24.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 22.12.2022	Did not appear Did not appear Did not appear 24.12.2022, 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 29.12.2022, 04.01.2023	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies in Korba District.
6	Parakh Kumar Kurrey	24.10.2022 12.12.2022	Did not appear 20.12.2022 23.12.2022	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies in Korba District.
7	Nikhil Chandrakar	24.10.2022 22.12.2022	Did not appear 24.12.2022, 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 29.12.2022, 04.01.2023	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies and maintain the data related to it.
8	Roshan Singh	04.12.2022 22.12.2022	Did not appear Did not appear	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies and maintain the data related to it.
9	Virendra Jaiswal @ Montu Jaiswal	03.01.2023	14.01.2023	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies in Surajpur District.
10	Rahul Singh	12.12.2022	26.12.2022 29.12.2022	He is an employee of Suryakant Tiwari who used to collect illegal levies in Surajpur

27 | Page

				District.
11	Ajay Naidu	03.01.2023	07.01.2023	He is childhood friend of Suryakant Tiwari and helped him in purchase of properties, construction works etc.

c) Partners of Suryakant Tiwari:

27

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
12	Jogendra Singh	24.10.2022 09.01.2023	01.11.2022, 02.11.2022, 05.11.2022, 12.11.2022, 13.11.2022 & 21.11.2022 19.01.2023	He is a business partner of Suryakant Tiwari.
13	Roop Kumar Chaudhary	24.01.2023	25.01.2023	He is a friend of Suryakant Tiwari. He received an amount of Rs. 1.5 Crore from Kailash Tiwari a day before ED searches.

d) Saumya Chaurasia and related persons

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
14	Saumya Chaurasia	14.10.2022 30.11.2022	20.10.2022, 27.10.2022, 01.11.2022 & 03.11.2022 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 09.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022 & 13.12.2022	She is one of the accused in this PC and her role is detailed in the succeeding paras.
15	Manish Upadhyay	12.10.2022 13.10.2022 27.11.2022 12.12.2022 10.01.2023	12.10.2022 & 13.10.2022 14.10.2022 Not appeared Not appeared Not appeared	He is neighbor and confidante of Saumya Chaurasia and her cash handler. Properties have also been purchased in his name

28 | Page

28

				by Saumya Chaurasia.
16	Deepesh Taunk	18.10.2022 14.01.2023 23.01.2023	21.10.2022, 26.10.2022, & 27.10.2022 Not appeared 24.01.2023, 26.01.2023, 28.01.2023	He is one of the accused in this PC and his role is detailed in the succeeding paras
17	Anurag Chaurasia	02.11.2022 12.12.2022 21.01.2023	17.11.2022, & 22.11.2022 Not appeared Not appeared	He is one of the accused in this PC and his role is detailed in the succeeding paras
18	Ashamani Modi	02.11.2022	16.11.2022	She is the mother-in-law of Saumya Chaurasia
19	Shanti Devi Chaurasia	02.11.2022 09.01.2023	16.11.2022 Did not appear	She is the mother of Saumya Chaurasia
20	Manoj Kumar Sinha	21.01.2023 21.01.2023	19.01.2023 23.01.2023	He is Managing Partner of Motel Madhuban where Anurag Chaurasia works as a Manager.
21	Bablu Saw	13.01.2023	19.01.2023	He is a friend of Anurag Chaurasia. Anurag Chaurasia and his family members received amount from the account of Bablu Saw.
22	Chandrashekhar Sinha	29.10.2022	29.10.2022	He is dealer through whom Deepesh Taunk sold fruits/vegetables in market & in whose name Deepesh Taunk has raised bills.
23	Rahul Mishra	16.11.2022	27.11.2022	He is an architect and worked for renovation of house pertaining to Shanti Devi Chaurasia and Saurabh Modi

e) Relating to Mining Staff

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
24	Shiv Shankar Nag, Deputy	21-11-2022	21.11.2022, 22.11.2022, 28.11.2022	He was posted as Deputy Director at Mining ...ent,

29 |

ईडी के इन तथ्यात्मक खुलासों के बाद सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई को होगी सजा।

पूछताछ में जुटी है। जबकि चिप्स घोटाले में दामाद का नाम सुर्खियों में है।

बताया जाता है कि जैसे-जैसे ईडी का फंदा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बघेल का कुनबा बेनकाब हो रहा है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों

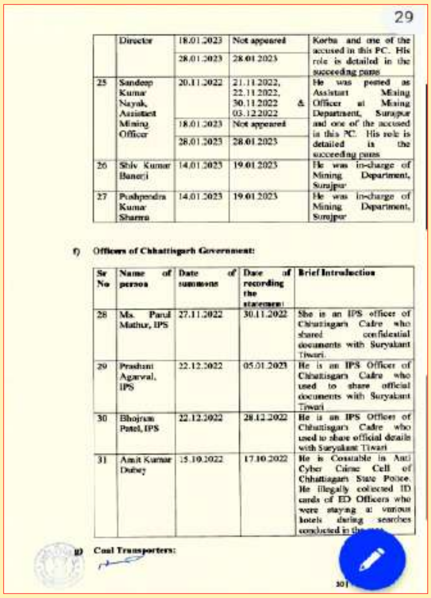

29

	Director	18.01.2023	Not appeared	Korba and one of the accused in this PC. His role is detailed in the succeeding paras
		28.01.2023	28.01.2023	
25	Sandeep Kumar Nayak, Assistant Mining Officer	20.11.2022	21.11.2022, 22.11.2022, 30.11.2022 & 03.12.2022	He was posted as Assistant Mining Officer at Mining Department, Surajpur and one of the accused in this PC. His role is detailed in the succeeding paras
		18.01.2023	Not appeared	
		28.01.2023	28.01.2023	
26	Shiv Kumar Banerji	14.01.2023	19.01.2023	He was in-charge of Mining Department, Surajpur
27	Pushpendra Kumar Sharma	14.01.2023	19.01.2023	He was in-charge of Mining Department, Surajpur

f) **Officers of Chhattisgarh Government:**

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
28	Ms. Parul Mathur, IPS	27.11.2022	30.11.2022	She is an IPS officer of Chhattisgarh Cadre who shared confidential documents with Suryakant Tiwari.
29	Prashant Agarwal, IPS	22.12.2022	05.01.2023	He is an IPS Officer of Chhattisgarh Cadre who used to share official documents with Suryakant Tiwari
30	Bhojram Patel, IPS	22.12.2022	28.12.2022	He is an IPS Officer of Chhattisgarh Cadre who used to share official details with Suryakant Tiwari
31	Amit Kumar Dubey	15.10.2022	17.10.2022	He is Constable in Anti Cyber Crime Cell of Chhattisgarh State Police. He illegally collected ID cards of ED Officers who were staying at various hotels during searches conducted in the...

g) **Coal Transporters:**

30 |

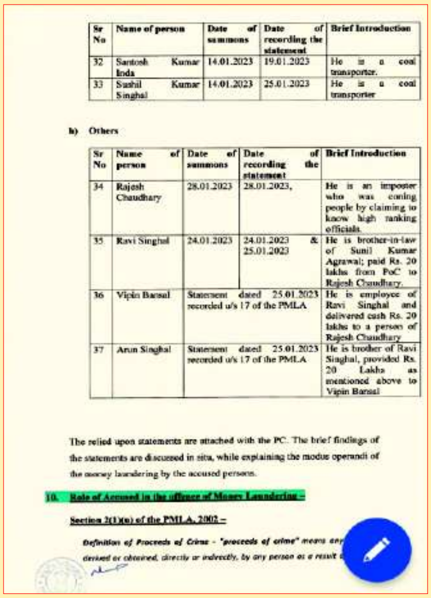

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
32	Santosh Kumar Inda	14.01.2023	19.01.2023	He is a coal transporter.
33	Sushil Kumar Singhal	14.01.2023	25.01.2023	He is a coal transporter

h) **Others**

Sr No	Name of person	Date of summons	Date of recording the statement	Brief Introduction
34	Rajesh Chaudhary	28.01.2023	28.01.2023,	He is an imposter who was coning people by claiming to know high ranking officials.
35	Ravi Singhal	24.01.2023	24.01.2023 & 25.01.2023	He is brother-in-law of Sunil Kumar Agrawal; paid Rs. 20 lakhs from PoC to Rajesh Chaudhary.
36	Vipin Bansal	Statement dated 25.01.2023 recorded u/s 17 of the PMLA		He is employee of Ravi Singhal and delivered cash Rs. 20 lakhs to a person of Rajesh Chaudhary
37	Arun Singhal	Statement dated 25.01.2023 recorded u/s 17 of the PMLA		He is brother of Ravi Singhal, provided Rs. 20 Lakhs as mentioned above to Vipin Bansal

The relied upon statements are attached with the PC. The brief findings of the statements are discussed in situ, while explaining the modus operandi of the money laundering by the accused persons.

10. Role of Accused in the offence of Money Laundering –

Section 2(1)(u) of the PMLA, 2002 –

Definition of Proceeds of Crime - "proceeds of crime" means any ... derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result ...

बयान दर्ज किए थे। इसके उपरांत सुपर सीएम सौम्या चौरसिया के खिलाफ पेश ED की चार्जशीट में पारुल माथुर समेत अन्य 2 IPS अधिकारियों का नाम शामिल है। इनमे से एक 2008 बैच के प्रशांत अग्रवाल SSP रायपुर के पद पर तैनात है। बड़ी विडंबना यह है की भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्था एंटी करप्शन ब्यूरो में आईपीएस पारुल साहू की पदस्थापना भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार ने कर दिया है। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार भ्रष्टाचार को कितना सपोर्ट करती है। 1000 करोड़ के ऊपर की जब्ती को लेकर भूपेश बघेल के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

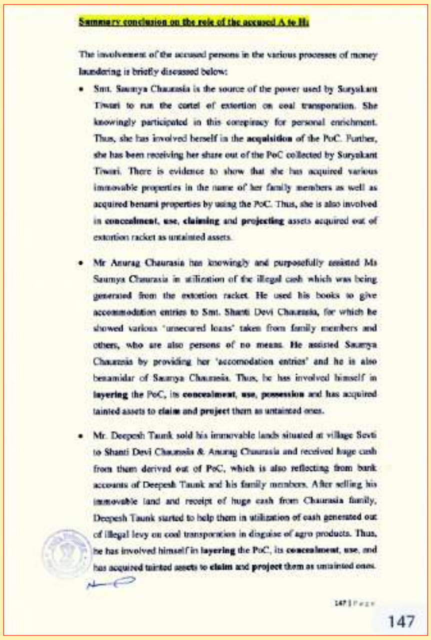

Summary conclusion on the role of the accused A to H:

The involvement of the accused persons in the various processes of money laundering is briefly discussed below:

- Smt. Saumya Chaurasia is the source of the power used by Suryakant Tiwari to run the cartel of extortion on coal transporation. She knowingly participated in this conspiracy for personal enrichment. Thus, she has involved herself in the **acquisition** of the PoC. Further, she has been receiving her share out of the PoC collected by Suryakant Tiwari. There is evidence to show that she has acquired various immovable properties in the name of her family members as well as acquired benami properties by using the PoC. Thus, she is also involved in **concealment**, **use**, **claiming** and **projecting** assets acquired out of extortion racket as untainted assets.
- Mr Anurag Chaurasia has knowingly and purposefully assisted Ms Saumya Chaurasia in utilization of the illegal cash which was being generated from the extortion racket. He used his books to give accommodation entries to Smt. Shanti Devi Chaurasia, for which he showed various 'unsecured loans' taken from family members and others, who are also persons of no means. He assisted Saumya Chaurasia by providing her 'accomodation entries' and he is also benamidar of Saumya Chaurasia. Thus, he has involved himself in **layering** the PoC, its **concealment**, **use**, **possession** and has acquired tainted assets to **claim** and **project** them as untainted ones.
- Mr. Deepesh Taunk sold his immovable lands situated at village Sevti to Shanti Devi Chaurasia & Anurag Chaurasia and received huge cash from them derived out of PoC, which is also reflecting from bank accounts of Deepesh Taunk and his family members. After selling his immovable land and receipt of huge cash from Chaurasia family, Deepesh Taunk started to help them in utilization of cash generated out of illegal levy on coal transportation in disguise of agro products. Thus, he has involved himself in **layering** the PoC, its **concealment**, **use**, and has acquired tainted assets to **claim** and **project** them as untainted ones.

147 | Page

147

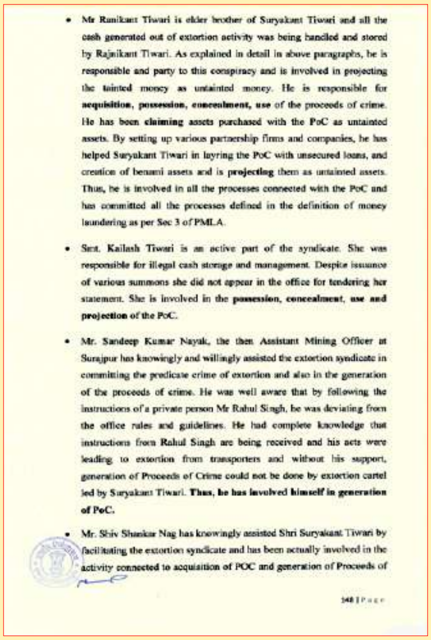

- Mr Ranikant Tiwari is elder brother of Suryakant Tiwari and all the cash generated out of extortion activity was being handled and stored by Rajnikant Tiwari. As explained in detail in above paragraphs, he is responsible and party to this conspiracy and is involved in projecting the tainted money as untainted money. He is responsible for **acquisition**, **possession**, **concealment**, **use** of the proceeds of crime. He has been **claiming** assets purchased with the PoC as untainted assets. By setting up various partnership firms and companies, he has helped Suryakant Tiwari in layring the PoC with unsecured loans, and creation of benami assets and is **projecting** them as untainted assets. Thus, he is involved in all the processes connected with the PoC and has committed all the processes defined in the definition of money laundering as per Sec 3 of PMLA.
- Smt. Kailash Tiwari is an active part of the syndicate. She was responsible for illegal cash storage and management. Despite issuance of various summons she did not appear in the office for tendering her statement. She is involved in the **possession**, **concealment**, **use and projection** of the PoC.
- Mr. Sandeep Kumar Nayak, the then Assistant Mining Officer at Surajpur has knowingly and willingly assisted the extortion syndicate in committing the predicate crime of extortion and also in the generation of the proceeds of crime. He was well aware that by following the instructions of a private person Mr Rahul Singh, he was deviating from the office rules and guidelines. He had complete knowledge that instructions from Rahul Singh are being received and his acts were leading to extortion from transporters and without his support, generation of Proceeds of Crime could not be done by extortion cartel led by Suryakant Tiwari. **Thus, he has involved himself in generation of PoC.**
- Mr. Shiv Shankar Nag has knowingly assisted Shri Suryakant Tiwari by facilitating the extortion syndicate and has been actually involved in the activity connected to acquisition of POC and generation of Proceeds of

148 | Page

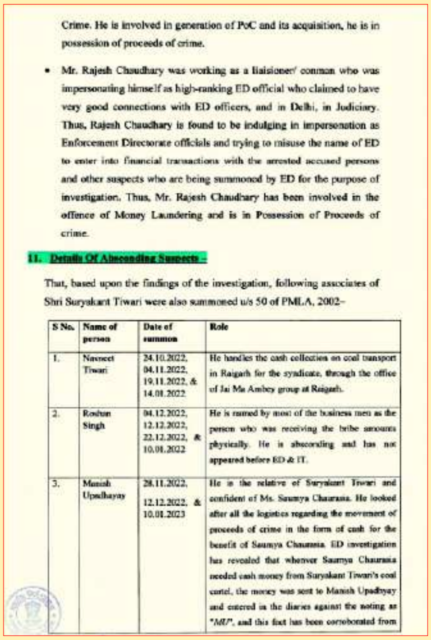

Crime. He is involved in generation of PoC and its acquisition, he is in possession of proceeds of crime.

- Mr. Rajesh Chaudhary was working as a liaisioner/ conman who was impersonating himself as high-ranking ED official who claimed to have very good connections with ED officers, and in Delhi, in Judiciary. Thus, Rajesh Chaudhary is found to be indulging in impersonation as Enforcement Directorate officials and trying to misuse the name of ED to enter into financial transactions with the arrested accused persons and other suspects who are being summoned by ED for the purpose of investigation. Thus, Mr. Rajesh Chaudhary has been involved in the offence of Money Laundering and is in Possession of Proceeds of crime.

11. Details Of Absconding Suspects –

That, based upon the findings of the investigation, following associates of Shri Suryakant Tiwari were also summoned u/s 50 of PMLA, 2002–

S No.	Name of person	Date of summon	Role
1.	Navneet Tiwari	24.10.2022, 04.11.2022, 19.11.2022, & 14.01.2022	He handles the cash collection on coal transport in Raigarh for the syndicate, through the office of Jai Ma Ambey group at Raigarh.
2.	Roshan Singh	04.12.2022, 12.12.2022, 22.12.2022, & 10.01.2022	He is named by most of the business men as the person who was receiving the bribe amounts physically. He is absconding and has not appeared before ED & IT.
3.	Manish Upadhayay	28.11.2022, 12.12.2022, & 10.01.2023	He is the relative of Suryakant Tiwari and confident of Ms. Saumya Chaurasia. He looked after all the logistics regarding the movement of proceeds of crime in the form of cash for the benefit of Saumya Chaurasia. ED investigation has revealed that whenver Saumya Chaurasia needed cash money from Suryakant Tiwari's coal cartel, the money was sent to Manish Upadhyay and entered in the diaries against the noting as "MU", and this fact has been corroborated from

चार्जशीट में मौजूद है प्रदेश के 04 आईपीएस अधिकारियों की कोल घोटाले में संलिप्तता।

से घिरी कांग्रेस कभी भी बघेल से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवा सकती है।

मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री बघेल के इस्तीफे के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में आरी डोंगरी आयरन ओर खदान आवंटन में केंद्र और राज्य सरकार को लगाया 01 हजार करोड़ से अधिक का चूना, गिरफ्तार आईएएस ने उगले कई चौंकाने वाले राज, आधा दर्जन आईएएस अफसरों समेत कुछ नेताओं पर कसता आईटी-ईडी का शिकंजा

छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की चार टीमों ने बस्तर में पहुंचकर जांच की। इस टीम में शामिल अफसर माइनिंग घोटालों की तहकीकात के मामलों में काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आदिवासी अंचल बस्तर में माइनिंग माफियाओं के काले कारनामे के साथ डीएमएफ फंड के भौतिक सत्यापन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दिल्ली से सीधे बस्तर भेजा गया है। यहाँ खनन घोटाले और डीएमएफ फंड के दुरुप्रयोग की शिकायतें सामने आयी हैं। सूत्रों का दावा है कि डीएमएफ फंड के दुरुप्रयोग को लेकर सिर्फ अभी रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से पूछताछ

कांग्रेस की लाज बचाने के लिए पार्टी विधायकों ने की सीएम भूपेश बघेल की घेराबंदी

भूपेश बघेल के खास अनिल टुटेजा है नान घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, हो सकती है जमानत रद्द

राज्य के सबसे बड़े 36 हजार करोड़ के नान घोटाले के तमाम सबूतों को आरोपी अनिल टुटेजा को ध्यान में रखते हुए रफा-दफा करने की कोशिशें की जा रही है। हाल ही में जो व्हाट्सअप चैटें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि नान घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने के लिए सीएम बघेल का कार्यालय तत्परता के साथ कार्य कर रहा था। इस घोटाले का मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा ही अदालती कार्यवाहियों को निर्देशित कर रहा था। इस गैर कानूनी कार्य में अनिल टुटेजा का बेटा यश टुटेजा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ईओडब्ल्यू के एसपी कल्याण एलेसिला, रायपुर के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख, आईजी आनंद छावड़ा, तत्कालीन गृहसचिव एवं सीएम कार्यालय में पदस्थ सचिव सुब्रत साहू, आईएएस समीर विश्नोई, कोयला माफिया सूर्यकांत तिवारी और राज्य की सुपर सीएम सौम्या चौरसिया आपस में आपराधिक कार्यो के लिए सामूहिक मकसद के साथ कार्य कर रहे थे। बताते हैं कि अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, चैतन्य बघेल, क्षितिज वर्मा समेत सभी आपस में एक-दूसरे के संपर्क में थे। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने 25 रूपये टन लेबी की अवैध वसूली, कोल परिवहन खनन घोटाला समेत गैर कानूनी कार्यो को अंजाम दिया था।

प्रदेश के अवैध शराब कार्टल में भी मुख्य भूमिका निभा रहे टुटेजा होंगे गिरफ्तार

की जा चुकी है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के चार अधिकारी और दो प्रमोटी आईएएस कतार में हैं। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ माइनिंग कार्पोरेशन की संदिग्ध गतिविधिओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए कुछ बड़ी टीम बस्तर, कांकेर और भानुप्रतापपुर भेजी गई हैं। भानुप्रतापपुर में भरपूर मात्रा वाली आयरन ओर की आरी डोंगरी खदान को औने-पौने दाम में सत्ताधारी दल के एक नेता को आवंटित किये जाने की पड़ताल शुरू हो गई है। यह मामला भी झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के परिजनों को खदानें आवंटित किये जाने की तर्ज पर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक राजनैतिक दल के लिए फंड इकट्ठा करने वाले आरजी नामक शख्स से जुडी कम्पनी को आरी डोंगरी खदान औने-पौने दाम में आवंटित कर दी गई थी। इससे केंद्र और राज्य सरकार को करीब एक हजार करोड़ का चूना लगाया गया है। बताते हैं कि इस खदान आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से आपराधिक दायरे में है। माइनिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कायदे कानूनों का

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान)घोटाला पांच साल बाद भी अभी तक किसी नतीजे तक नही पहुँचा है। इस घोटाले के सूत्रधार और प्रमुख आईएएस आरोपी अनिल टुटेजा और आईएएस आलोक शुक्ला सरकारों की मेहरबानियों से लाभ के पदों पर आसीन हैं। जबकि गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालतों ने इन्हें आरोपी मान लिया है। यह छत्तीसगढ़ इतिहास का काला अध्याय होगा कि अदालतों ने आरोपी मानने के बाद राज्य सरकार इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान किए हुए है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का नान घोटाला 2015 में उजागर हुआ था। जबसे लेकर अब तक इस घोटाले को लेकर जॉच एजेंसियां काम कर रही हैं। एक-एक कड़ी को जोड़कर घोटाले की जड़ तक पहुँच भी गई हैं। इन सबके बावजूद घोटाले के मास्टर माइंड अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार भी नहीं चाहती है कि घोटालों की जाँच नतीजे तक पहुँचे। जब राज्य में डॉ. रमन सिंह की सरकार थी तब विपक्ष में रहते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने इस घोटाले को खूब उछाला था। विधानसभा तक इस घोटाले को लेकर गए थे। अब तक मुख्यमंत्री नान घोटाले के लिए

भ्रष्टाचार की सिलसिलेवार खुलती परतों से बघेल का चेहरा बेनकाब

उल्लंघन कर किसी खास व्यक्ति को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाया था। इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। कहा जाता है कि खास लाभार्थी को खदान आवंटन के लिए कई बार अनुचित प्रयास किये गए। इसके लिए पूर्व निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया को कोल परिवहन घोटाले की तर्ज पर ऑफलाइन किया गया। फिर टेंडर फार्म अपने ही लोगों को उपकृत करने के लिए जारी किये गए। शेष प्रतियोगियों को टेंडर फार्म नहीं उपलब्ध कराये गए। उन्हें इसके लिए परेशान किया

आरी डोंगरी खदान आवंटन में हुआ भारी भ्रष्टाचार, ईडी जाँच में जुटी

नान के खिलाफ कांग्रेसियों ने बोला था हल्ला बोल

सन् 2015 में जब नान घोटाला उजागर हुआ था, तब विपक्ष में रहते हुए प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने हल्ला बोला था। इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गए थे। प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख कर मामले की सीबीआई, ईडी से जांच कराने की मांग की थी। आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अब कांग्रेस सरकार घोटाले को लेकर क्या कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नान घोटाले का प्रचार–प्रसार किया और आज वह इस घोटाले के चलते सत्ता पर आसीन हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हल्ला बोला था। जब तो वर्तमान में कांग्रेस घोटाले के दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि घोटाले के दो प्रमुख आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए रखा है। इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी बहाल कर दिया है। कांग्रेस की इस दोहरी नीति से तो यही लगता है कि किसी मामले को खूब उछाल कर सत्ता हासिल कर लो और फिर मामले को भूल जाओं।

चिट्ठीबाजी और बयान दे रहे हैं कि ईडी इसकी जांच करें। क्यों न राज्य सरकार स्वयं ही यह मामला सीबीआई को सौंप दे ताकि केन्द्रीय एजेंसियां प्रदेश के गरीबों का 36 हजार करोड़ डकारने वाले मगरमच्छों को पकड़ सके।

कांग्रेस को भारी पड़ सकता है भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 विधानसभा चुनाव

गया। माइनिंग दफ्तर में लठैतों की तैनाती कर आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। सूत्रों की माने तो बलपूर्वक हासिल की गई आरी डोंगरी खदान आवंटन की हकीकत आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य ने ईडी से साझा की है। इसकी तस्दीक गिरफ्तार आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई ने भी की है। बताया जाता है कि इस मामले में अन्य आईएएस अधिकारियों के लपेटे में आने के आसार बढ़ गए हैं। आरी डोंगरी आयरन ओर खदान कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर तहसील के कचही

उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ ही शुरू हो जायेगी बघेल की उलटी गिनती

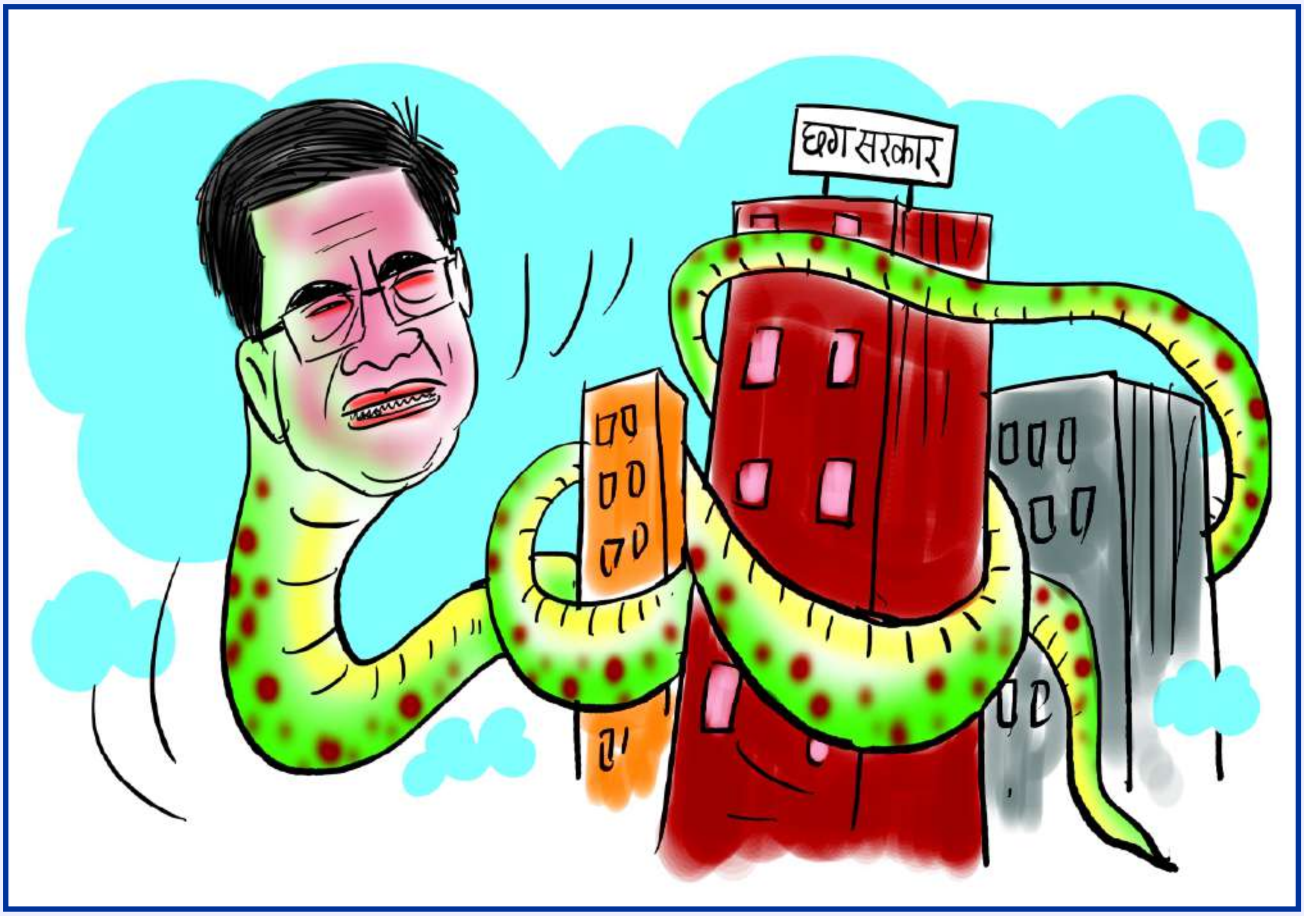

36 हजार करोड़ के धोटाले का आरोपी अनिल टुटेजा अब शराब कार्टल का भी किंगपिंग बन गया है। ईडी के छापे के बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल वह अभी जमानत पर है।

धोखाधड़ी और जालसाजी के लगाए आरोप

छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली देश भर में चर्चित हो रही है। आईटी–ईडी समेत कई केंद्रीय एजेंसियां सरकार की गोद में बैठे अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों और उनके कारोबारियों के गिरेबान में आए दिन हाथ डाल रहे हैं। काले कारनामों में लिप्त कई सरकारी अधिकारियों की काली कमाई के साथ–साथ उनकी आपराधिक कार्यप्रणाली भी सामने आ रही है। भले ही छत्तीसगढ़ सरकार और उसके नेता केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही को राजनैतिक करार दे रहे हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और अनुपातहीन सम्पत्तियों के मामले तस्दीक कर रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके चलते आम जनता का हाल–बेहाल है। राज्य की गरीब और जरूरतमंद जनता की सरकारी तिजोरी में जमा होने वाली रकम को कई अधिकारी ऐसे लूट रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में सत्ता में परिवर्तन सिर्फ उनके हितों और अवैध कमाई के लिए ही हुआ है। आदिवासी और सामान्य इलाकों में खर्च होने वाली अरबों की सरकारी रकम मुख्यमंत्री बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी समेत उसके कई नाते रिश्तेदारों की तिजोरी में चले गई। ऐसे अधिकारियों और कारोबारियों को प्राप्त सरकारी संरक्षण राज्य के छले गए आम वोटर देख रहे हैं। हद तो तब हो रही है, जब जायज मामलों को लेकर राज्य की पुलिस वैधानिक कार्यवाही करने के बजाए प्रभावशील आरोपियों के सामने ही दंडवत हो जाए। नतीजतन पीड़ितों को इन्साफ के लिए अपनी गाढ़ी कमाई कोर्ट–कचहरी के चक्कर में खर्च करनी पड़ रही है। वैधानिक मामलों में भी छत्तीसगढ़ पुलिस की बेरुखी के चलते पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पुलिस के रवैये से परेशान होकर पीड़ित कोर्ट में परिवाद दाखिल करने को मजबूर हैं। जबकि अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के लिए नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार प्राप्त है।

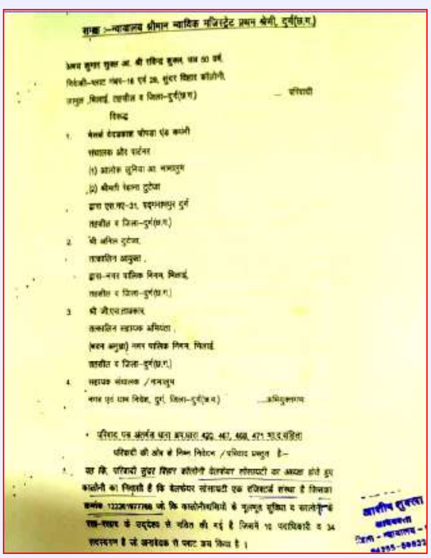

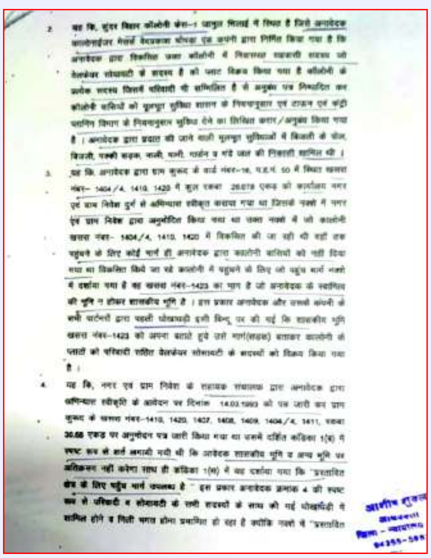

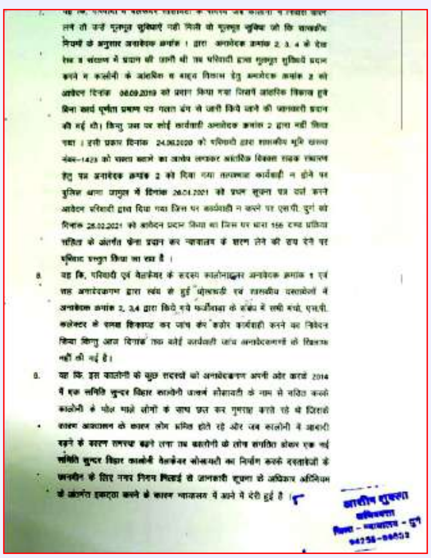

अनिल टुटेजा, रेहाना टुटेजा के खिलाफ नोटिस

गांव के अंतर्गत आती है। यह खदान 167 हैक्टेयर भू-भाग से ज्यादा इलाके में फैली हुई है। सूत्रों का दावा है कि इसे आरजी की किसी कंपनी को आवंटित करने का फैसला राज्य सरकार ने किया था। छत्तीसगढ़ मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन

बताते हैं कि सरकार को राह दिखाने वाले कई चर्चित अफसर और उनका कुनबा आम जनता पर भारी पड़ रहा है। उनके क्रियाकलापों से जहां सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है। वही आम जनता का अमन चैन भी लगातार छिन रहा है। पीड़ितों का मानना है कि कांग्रेस का दावा अब होगा न्याय सिर्फ शिगूफा तो नहीं दरअसल बीते चार सालों में उन अफसरों की पौ बारह है ,जो सरकार चला रहे हैं। उनकी काली करतूतों की सुध लेने वाला कोई नहीं। यह भी बताते हैं कि कारोबारी अफसरों का व्यापार कई जिलों में फैला हुआ है। फिलहाल पीड़ितों को अब अदालत से ही राहत की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का जनहित से जुड़ा एक मामला अदालत में सुर्खियां बटोर रहा है। पीड़ितों ने परिवाद दाखिल कर अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। इस परिवाद में आरोपी बनाए गए लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467,468,471 अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। दुर्ग के अभय कुमार शुक्ला–जामुल भिलाई निवासी ने एक परिवाद दाखिल कर मेसर्स वेदप्रकाश चोपड़ा एंड कंपनी और उनके पार्टनर अलोक लुनिया एवं श्रीमती रेहाना टुटेजा–दुर्ग, अनिल टुटेजा–तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई, जीएस ताम्रकार तत्कालीन सहायक अभियंता दुर्ग और सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश दुर्ग के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। परिवाद में कहा गया है कि फरियादी सुन्दर विहार कालोनी वेलफेयर सोसायटी का अध्यक्ष है। इस सोसायटी में 10 पदाधिकारी और 34 सदस्यगण हैं। इन्होंने श्रीमती रेहाना टुटेजा से प्लाट लिया है। प्लाट की रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेजों में रेहाना टुटेजा और अलोक लुनिया ने कॉलोनीवासियों को नियमानुसार तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया था। इसके लिए पीड़ितों ने मोटी रकम दोनों को चुकाई थी। परिवाद के अनुसार बिल्डर ने सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, निकासी, सैप्टिक टैंक, ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को जुटाए बगैर नगर निगम एवं नगर ग्राम निवेश विभाग से तमाम अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल कर लिए। यही नहीं कई एकड़ में फैली इस आवासीय कालोनी के बंधक बनाए गए प्लॉटो को भी मुक्त करा लिया। परिवाद में बताया गया है कि मूलभूत सुविधाओं को बगैर जुटाए इस बिल्डर को शासन ने स्वतंत्र कर दिया। जबकि पीड़ित शासन के अधिकारियों और विभागों को असलियत से वाकिफ कराते रहे। यहां तक कि पीड़ितों के साथ हुई धोखाधड़ी के सबूत और शिकायत सौंपे जाने के बावजूद पुलिस ने मामले की सुध तक नहीं ली। बताते हैं कि अधिकारियों के प्रभाव में पुलिस ने मामले को सिविल मैटर करार देकर किनारा कर लिया। पीड़ितों के मुताबिक धोखाधड़ी के इस तरह के कई मामलों में पुलिस पहले भी अपराध दर्ज कर अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कर चुकी है, लेकिन इस मामले की पुलिस ने सुध तक नहीं ली। पीड़ितों की दलील है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अधिकारी अनिल टुटेजा के प्रभाव के चलते बिल्डरों को उपकृत किया गया है, उन्हें कई फर्जी दस्तावेज टुटेजा के हस्तक्षेप से प्राप्त हुए हैं। रेरा भी चुप रहा। परिवाद में कहा गया है कि पीड़ितों ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से यह प्लाट ख़रीदे थे, लेकिन ठगे गए। पीड़ितों ने हैरानी जताई की बगैर भौतिक सत्यापन किए टुटेजा के निर्देश पर अधिकारियों ने कागजी घोड़े दौड़ा दिए। उनके मुताबिक प्रभावशील बिल्डरों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते उन्हें दस्तावेज जुटाने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज जुटाकर अदालत की शरण ली है। जगत विजन ने परिवाद में आरोपी बनाए गए लोगों से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

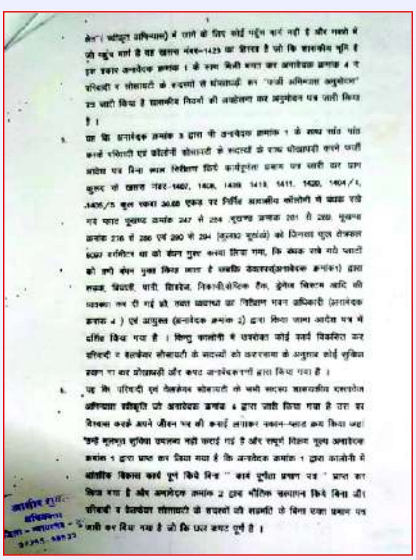

ने इसके तहत कई बार टेंडर निकाले और किसी न किसी कारण से फिर टेंडर निरस्त कर दिए थे। आखिरकार खदान आवंटन से जुडी तय प्रक्रिया को दरकिनार कर अपने परिजनों को उपकृत कर शासन के राजस्व का नुकसान किया गया। इस तरह से एक

सीडी काण्ड : मुख्य साजिशकर्ता विनोद वर्मा को होना चाहिए सलाखों के पीछे, भूपेश बघेल सरकार में खा रहे मलाई

कहीं रिंकू खनूजा की हत्या, सीडी काण्ड के आरोपियों ने तो नहीं करवाई?

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी काण्ड के मास्टर माइंड पत्रकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साले विनोद वर्मा थे। जिन्हें छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की फर्जी अश्लील सीडी का षडयंत्र रचने के आरोप में गाजियाबाद से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विनोद वर्मा वर्तमान में जमानत पर हैं और सीएम बघेल के सलाहकार बने हुए हैं। इसी मामले में सीएम भूपेश बघेल भी जमानत पर है। इन पर भी सीडी काण्ड में संलिप्त होने का आरोप है। सीडी स्कैंडल कांड में एक नया मोड़ तब आया जब दबाव में आकर रिंकू खनूजा ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरतलब है कि 27अक्टूबर 2017 को कथित अश्लील सीडी का मामला सामने आया था। जिसके बाद राजनीति गर्मा गयी। चूंकि यह सीडी प्रदेश के एक बीजेपी के कद्दावर नेता राजेश मूणत की थी। तब बीजेपी सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान किया था इसके बाद जांच शुरू की थी। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनीं और भूपेश सरकार ने सीडी कांड को लेकर एसआईटी का गठन किया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को क्लीनचिट दी जा सके। फर्जी सेक्स सीडी कांड के तमाम गवाहों को प्रभावित करने में कोई

और फर्जीवाड़ा कर आरजी से जुड़ी एक अन्य कम्पनी को भी फायदा पहुंचाने की कवायत की गई। सूत्रों के मुताबिक उस कम्पनी के नाम पर कोल खदान आवंटन प्रक्रिया के लिए षड़यंत्र किया गया। यही नहीं भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी को

क्या सीडी काण्ड के आरोपियों को बचाने के लिए रिंकू खनूजा की हत्या की गई, जिसे आत्महत्या दिखाया गया

कसर नही छोड़ी थी। बताया जा रहा है कि सेक्स सीडी कांड के मुख्य आरोपी रिंकू खनूजा की आत्महत्या का मामला भी बेहद संगीन है। सूत्रों के मुताबिक रिंकू की आत्महत्या के मामले को लेकर उनके परिजनों ने पहले हत्या का शक जताया था। लेकिन रायपुर के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने आत्महत्या की थ्योरी को लाद दिया था। बताते हैं कि हत्या के पहलुओं पर विचार किये बगैर ही शेख आरिफ ने रिंकू खनूजा की मौत को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अब उनकी चैट बता रही है कि रिंकू खनूजा की मौत स्वाभाविक नही थी। बताते हैं कि सेक्स सीडी कांड के आरापियों और ईडी के

बाक्साइट सप्लाई के लिए भी खदान आवंटन किये जाने की अनुचित कवायत की गई। यह भी बताया जा रहा है कि आदिवासी इलाकों में अरबों का डीएमएफ फंड अधिकारियों ने ही डकार लिया। दंतेवाड़ा समेत अन्य इलाकों में डीएमएफ

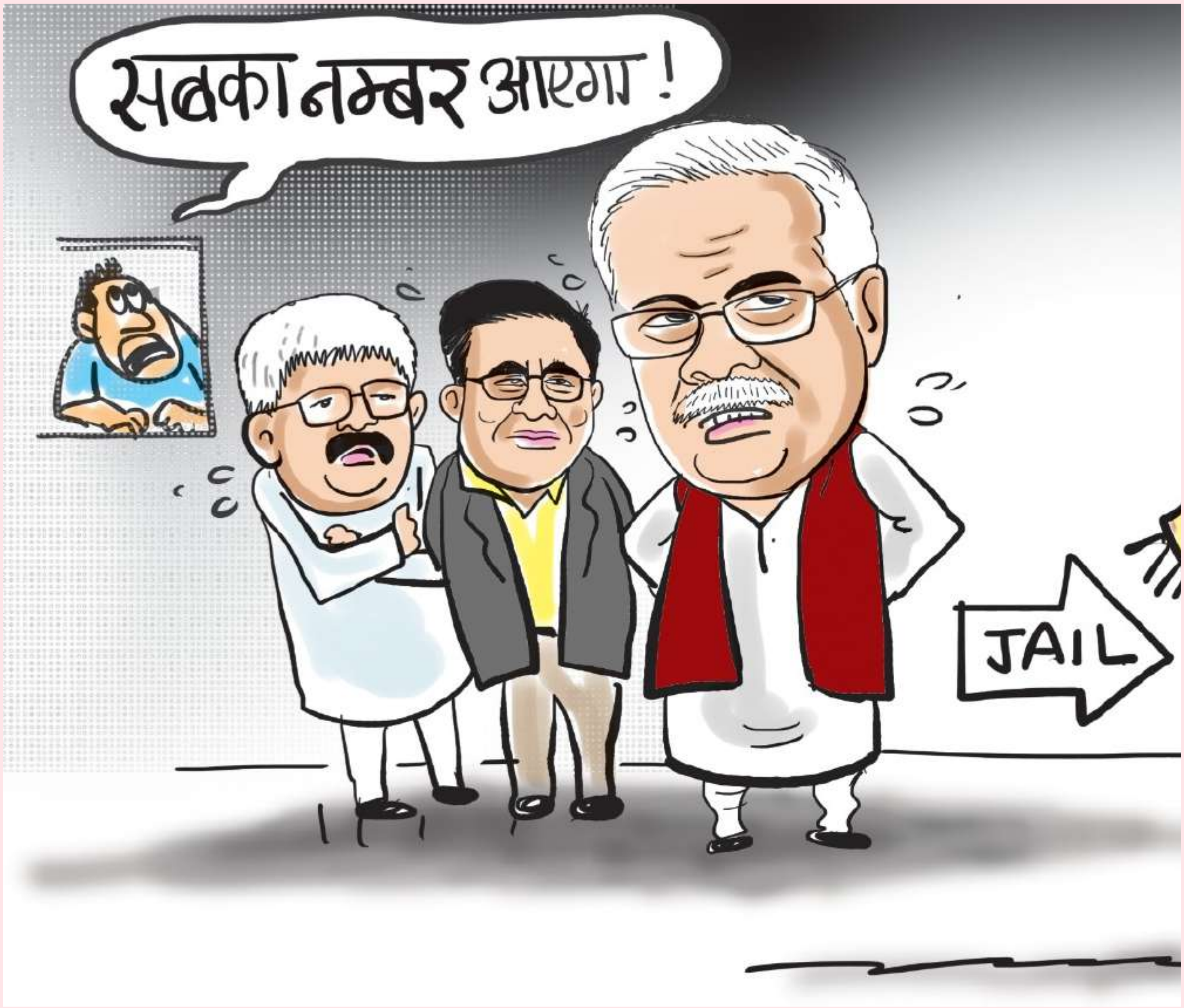

आरोपियों के साथ मिलकर आरिफ शेख आखरी वक्त तक रिंकू खनूजा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब पर कार्य करते रहे थे। नतीजतन तक रिंकू खनूजा की मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। बताया जाता है कि रिंकू खनूजा के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए उसे मौत के घाट उतारा गया था। यह भी बताया जाता है कि रिंकू खनूजा का पोस्टमार्टम विधि संगत तरीके से नही कराया गया था ताकि भविष्य में उसकी मौत के सबूतों को अस्तित्व में नही लाया जा सके। लेकिन अब

फंड का बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। यहाँ राज्य शासन की मद से जिन कार्यो के लिए राशि खर्च की गई, उसी स्थान पर विकास कार्यो और सफाई सुंदरता के लिए डीएमएफ फंड से कई करोड़ खर्च कर दिए गए। बस्तर के

क्या है मामला

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2017 को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता प्रकाश बजाज नामक व्यक्ति है। प्रकाश बजाज ने आरोप लगाया है कि कोई व्यक्ति, जो अज्ञात है, उसने दिल्ली से फोन किया है कि उसके आकाओं की सीडी मेरे पास है और यदि वह मुझे पैसा नहीं देगा तो उसकी सीडी जारी कर दी जाएगी। उस एफआईआर में प्रकाश बजाज ने न तो फोन करने वाला का नंबर बताया है, न ही फोन करने वाले की आवाज का विवरण दिया है और न ही फोन करने वाले व्यक्ति का नाम बताया है। 2 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ पुलिस हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पहुंचते ही उसने दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश की पुलिस को साथ में लेकर रात तकरीबन 2 बजे पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। विनोद वर्मा को गिरफ्तार करने के उपरांत उसे गाजियाबाद कोर्ट में प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ पुलिस से जब गाजियाबाद के न्यायालय ने सबूत मांगे तब पुलिस ने 2 घंटे का समय लेकर बाजार से सीडी खरीद लायी। उन सीडी को विनोद वर्मा द्वारा बनाई गई बताते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। विनोद वर्मा की तरफ से सतीश चंद्र वर्मा अधिवक्ता बिलासपुर उच्च न्यायालय पैरवी कर रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोर्ट में कोई भी अन्य वस्तु, तथ्य, सामग्री एवं सबूत नहीं पेश किया है। माननीय न्यायालय ने दो बार पुलिस से कह दिया है कि आपके पास जो तथ्य, सबूत हैं प्रस्तुत करें, परंतु पुलिस के हाथ खाली हैं। वही विनोद वर्मा ने माननीय न्यायालय में प्रथम दिन प्रस्तुत करने पर रायपुर में उन्होंने आवेदन धारा 156(3) अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया है। वक्त आवेदन में उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा मंत्री राजेश मूणत के इशारे पर उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि विनोद वर्मा ने अंतागढ़ सीडी कांड को उजागर किया था और अंतागढ़ सीडी कांड में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। इन बातों से रमन सिंह व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी रखते हैं।

आरिफ शेख की चैट सामने आने के बाद मामले की हकीकत के भी जल्द सामने आने के आसार बड़ गये हैं। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई जल्द ही इस मामले की बंद फाईल खोलने की तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल और उनकी सरकार के आपराधिक कृत्यों से लोगों को हो रही है। दरअसल पहली बार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के काले कारनामे दस्तावेजों के साथ सामने आ रहे हैं। इनसे जुडी चैट के सामने आने के बाद जनता का भरोसा भूपेश बघेल पर से उठने लगा है। इन चैटों में अनिल कुमार टुटेजा और आईपीएस आरिफ शेख के बीच इस मामलों को लेकर काफी गोपनीय बातें सामने आ गई। टुटेजा आरिफ शेख जो कि तब ईओडब्ल्यू/एसीबी में पदस्थ थे, को निर्देश देते थे कि कैसे इस मामले के गवाहों को रिंकू खनूजा के मामले में फंसाया। अब तो लगता है कि रिंकू खनूजा की हत्या तो नहीं करवाई गई। यकीनन अब संदेह उठता है कि कहीं रिंकू खनूजा की हत्या इस केस के आरोपियों ने तो नहीं करवाई।

आलावा कोरबा, चांपा, जांजगीर समेत अन्य जिलों में भी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने तो डीएमएफ फंड की रकम से कल्याणकारी कार्य करने के बजाय खुद का कल्याण किया। उन्होंने यह रकम बगैर कार्य कराये अपनी जेब में

सीएम भूपेश बघेल की हिलने लगी कुर्सी

कभी भी छोड़ना पड़ सकता है पद

छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन घोटाले की आंच और जॉच अब सीएम बघेल और उनके पुत्र चेतन्य बघेल पर टिक गई है। ईडी ने चौतरफा छापेमारी कर परिवहन घोटाले के असल गुनहगारों का चेहरा बेनकाब कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय ही भ्रष्टाचार के घेरे में है। मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई से ही एक–दो नही बल्कि हाईकोर्ट के तीन जज कार्य कर चुके हैं। अब चौथे जज बी. सेम कोसी की अदालत में सौम्या की जमानत को लेकर ईडी और बचाव पक्ष के बीच दलीलों का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। सौम्या की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। जबकि ईडी की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर के.एन. राजू ने अपनी दलीले पेश की। ईडी की सक्रियता बताती है कि कोल परिवहन घोटाले में वो अब अपनी कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने में जोर–शोर से जुट गई है। राज्य में ईडी के चौतरफा छापों से हड़कंप है। एक दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी कारोबारी ठेकेदार और माफिया ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें से चौंकाने वाले संदेही और कारोबारी अफसर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पाये गये हैं। ईडी ने ऐसे अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर घोटाले से जुडे कई दस्तावेज और हिसाब–किताब के डिजीटल साक्ष्य भी जप्त किये हैं। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर एजेंसियों का शिकंजा लगतार कंसता जा रहा है। कोल परिवहन घोटाले की फेहरिस्त में अब तक जितने आरोपी और संदेही सामने आये हैं उनका सीधा नाता सीएम बघेल और उनके परिजनों एवं नाते–रिश्तेदारों के साथ पाया गया है। बताते हैं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इन संबंध में कई डिजीटल साक्ष्य पेश किये हैं। ये साक्ष्य इन दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। नौकरशाहों और ईडी एवं सीबीआई आरोपियों के साथ आपराधिक कृत्यों से जुड़ी कई चैट सामने आने के बाद प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं की विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह पहला मौका है जब सत्ताधारी दल के नेताओं और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने खुलेआम घोटालों की झड़ी लगा दी हो। इसके बावजूद भी सरकार और उसकी वैधानिक एजेंसियों हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। कृषि प्रधान इस प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में पूरे देश में पहचान मिली थी लेकिन अब यह प्रदेश घोटालों की वजह से जाना पहचाना जा रहा है। सीएम कार्यालय के कठघरे में आने से सीएम बघेल पर सीधे तौर पर उंगलिया उठने लगी हैं। ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीएम बघेल पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने इन आरोपों की पुष्टि के लिए कई दस्तावेजी प्रमाण भी जुटाए हैं। सत्ताधारी दल में भ्रष्टाचार को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है।

डाल ली। सरकारी अभिलेखों में इस रकम का कोई ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। उन

अफसरों को अपने कार्यकाल में रकम वापसी का पर्याप्त मौका भी मिला था।

लेकिन अधीनस्थ अफसरों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाये जाने के बावजूद सरकारी

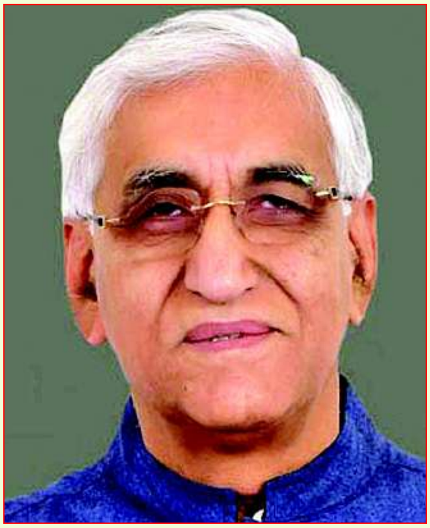

छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता लगातार दिल्ली तलब

बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा में सीएम बघेल के कारोबारी अधिकारियों और करीबियों के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सक्रियता दिखाई है। उन्होंने सदन में भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर सीएम बघेल के लिए नई मुसीबत खड़ा कर दी है। बताते हैं कि सीएम बघेल के करीबियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से प्रदेश में कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई विधायक और नेता भूपेश बघेल के रवैये से सख्त नाराज बताये जाते हैं। उनकी दलील है कि सीएम कार्यालय में पनप रहे भ्रष्टाचार से पार्टी की छवि खराब हो रही है। सीएम को भले ही इसी चिंता न हो लेकिन मैदानी इलाकों में भ्रष्टाचार की वजह से विकास कार्य, जनता के साथ किये गये वादों को लेकर भी लोगों की नाराजगी सामने आने लगी है। संकल्प पत्र में किये गये वादों को पूरा नही करने के चलते विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति लगातार नाजुक हो रही है। लिहाजा कई विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम बघेल के बजाय कांग्रेस के ज्यादातर विधायक मोहन मरकाम के अपने नेता के रूप में देख रहे है। उन्हें उम्मीद है कि घोटालों का मुख्यमंत्री चंद दिनों में ही अपनी राह पकड़ लेगा।

राज्य के आला नेताओं को किया दिल्ली तलब

छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी में आई तेजी से राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर है। राज्य के कई बड़े नेता लगातार दिल्ली तलब किए जा रहे है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस प्रभारी शैलजा की एक रिपोर्ट के बाद आलाकमान कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके तहत वरिष्ठ नेता चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को दिल्ली तलब कर दिया गया है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही दिल्ली दरबार में हाजिर थे। ऐसे समय पार्टी के धुरंधर नेताओं का दिल्ली दौरा चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की मुलाकात क्या रंग दिखायेगी यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन राज्य के कोल खनन परिवहन घोटाले को आंच दिल्ली दरबार पहुंचने से पहले पार्टी उसके इलाज में जुट रही है।

रकम की वापसी नहीं की गई। फिलहाल आईटी-ईडी के संयुक्त प्रयास से छत्तीसगढ़ में जांच अधिकारी धनशोधन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के

कोल परिवहन जैसे और कई घोटालों की जड़ें खोद रही है ईडी

रानू साहू

जे.पी. मौर्य

छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं और अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया है। सरकार के संकट मोचक मुख्यमंत्री बघेल और उनके कुनबे के बचाव में उतर गए हैं। ऊपर से बचे कुचे संदेहियों और ईडी के बीच तू डाल–डाल में पात–पात का खेल जारी है। राजगढ़ कलेक्टर रानू साहू, आइएएस जेपी मौर्य दर्जनों अफसरों और कारोबारियों से ईडी की पूछताछ हो चुकी है और गिरफ्तारी की तलवार चल रही है। अंदेशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि कोल परिवहन घोटाले के अलावा भी कई और अपराधों की जड़ खोद रही है। इसके डीएमएफ फण्ड घोटाला और कांकेर की आरी डोंगरी खदान आवंटन का मामला सुर्खियों में है। डीएमएफ फंड में करोड़ों के घपले और सरकारी रकम की बंदरबांट को लेकर आधा दर्जन आईएएस अफसर जांच के दायरे में हैं। उधर कांकेर की आरी डोंगरी खदान को आने–पौने दाम में एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री बघेल के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। बताते हैं कि कोरोनाकाल में आरी डोंगरी खदान को औने–पोने दाम में आरजी नामक शख्स को सौंप दिया। यहां भी टेंडर की ऑनलाईन प्रक्रिया को आफलाईन किया गया था। केन्द्र और राय सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगी है। सूत्र यह भी बताते हैं कि अपनों को खदान आवंटित करने के मामले में तत्कालीन डायरेक्टर माईनिंग जेपी मौर्य और आईएएस समीर विश्नाई से घण्टों पूछताछ की है। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, कोल कारोबारी सुनील अग्रवाल और आईएएस समीर विश्नोई के खिलाफ लगभग 08 हजार पन्नों का चालान रायपुर में ईडी की विशेष अदालत में पेश किया है। इस चालान में प्रस्तुत किये गए तथ्यों से मुख्यमंत्री बघेल और उनकी टोली पूरी तर से बेनकाब हो चुकी है। अब यह देखना गौरतलब होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बघेल को ठिकाने लगाती है या फिर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के साढ़े 04 साल के कार्यकाल में अरबों का घोटाला सामने आया है। सेन्ट्रल फंडिंग हो या फिर राज्य शासन की योजनाएं, शायद ही ऐसा कोई महकमा बचा हो जहाँ बड़े

छत्तीसगढ़ के 22 आईएएस समेत 100 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज

छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 22 अधिकारियों समेत विभिन्न विभाग में पदस्थ 100 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। विधानसभा में विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के 22 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, जमीन का गलत तरीके से आवंटन, चहेती फर्मो को आर्थिक लाभ पहुंचाने, खरीदी में गड़बड़ी के मामले शामिल हैं। इनमें आईएएस रघुनाथ प्रसाद, आरपी यादव, अजय नाथ, एनपी तिवारी, एमके राउत, एचपी किंडो, राबर्ट हरंगडोला, सुब्रत साहू, टीएस छतवाल, बाबूलाल अग्रवाल, वीके धुर्वे, डॉ। आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, रणबीर शर्मा और जनक प्रसाद पाठक शामिल हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि 16 मामलों में विवेचना लंबित है, जबकि तीन मामलों में खात्मा और एक मामला खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, ईओडब्ल्यू, एसीबी, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, वाणिय कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं।

जांच करने वाले विभाग भी जांच के दायरे में

भ्रष्टाचार की जांच करने वाले विभाग इओडब्लू और एसीबी विभाग में भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। आखिर जब इसी विभाग के अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग के मामले हैं तो आय से अधिक सपत्ति और रिश्वत के मामले की जांच भी किसी तरह से होती होगी। छत्तीसगढ़ शासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के अक्सर आरोप लगते रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई किए जाने के दावे भी शासन-प्रशासन से आए दिन किए जाते हैं। लेकिन सच यह है कि इन अधिकारियों पर शायद ही कभी किसी प्रकार का एक्शन लिया गया हो। छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितता और दूसरी गड़बड़ी किए जाने का आरोप हैं।

पैमाने पर घोटाले सामने ना आ रहे हो। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की काली कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अपराधिक वारदातें सामने आई हैं। केंद्रीय एजेंसियां इन अफसरों पर लगाम लगाने के लिए एड़ी-

मुख्यमंत्री बघेल और उनके कुनबे तक पहुंची ईडी, बेटे से हुई पूछताछ

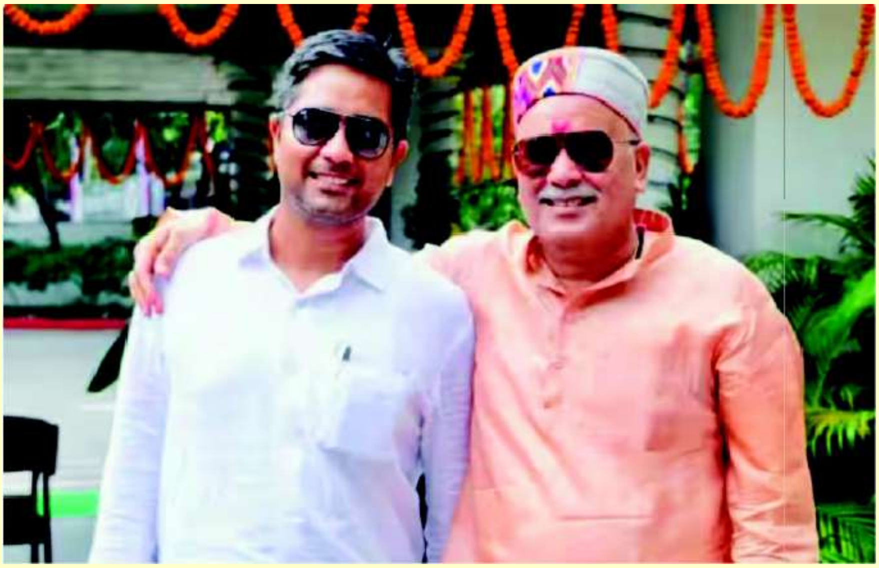

छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया की ईडी के गिरफ्त में आने से मुख्यमंत्री बघेल की और उनकी टोली की असलियत जनता के सामने आ गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के कई अधिकारी सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग और सरकारी तिजोरी पर किस तरह से हाफ साफ कर रहे थे, इसका भी खुलासा हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सौम्या चौरसिया करोड़ों की ब्लैकमनी इकट्ठा कर रही थी और मुख्यमंत्री बघेल को यह संज्ञान में न हो, यह तथ्य भरोसे लायक नही लगता है और मुख्यमंत्री बघेल सौम्या चौरसिया के काले कारनामों से वाकिफ न हो। ईडी के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के पुत्र चेतन्य बघेल से पूछताछ कर कोई बड़ी कार्यवाहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री बघेल और उनके कुनबे से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। चिप्स में दामाद बाबू की अवैध वसूली का काला चिट्ठा गिरफ्तार आरोपियों ने ईडी के संज्ञान में लाया है। इसकी भी पड़ताल जारी है। जाहिर है छत्तीसढ़ में अरबों की अवैध वसूली, मनी लांड्रिंग, विदेशों तक में ब्लैकमनी की आवाजाही को लेकर मुख्यमंत्री बघेल से भी पूछताछ के आसार हैं।

चैतन्य बघेल पर ईडी की सख्ती

सूत्रों के अनुसार ईडी ने हाल ही में चैतन्य बघेल को अपने दफ्तर में बुलाया था। ईडी की पूछताछ के दौरान चैतन्य बघेल पर सख्ती दिखाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान चैतन्य बघेल ने अपने राजनैतिक रौब को दिखाने की कोशिश की वहीं ईडी ने भी अपने तेवर दिखाते हुये चैतन्य बघेल के साथ काफी सख्ती दिखाई।

चोटी का जोर लगा रही हैं। उनके कदमों पर रोक लगाने के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे कैडर के अफसर रोड़ा अटका रहे हैं। ये अफसर डंके की चोट पर अवैध फ़ोन टेपिंग और पत्रकारों पर फर्जी मुक़द्दमे दर्ज कर उन्हें जेल में ठूस रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से जनता के सपनों पर पानी फिर रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महिनों का वक्त बचा है। कांग्रेस अपने वादों से तेजी से मुकर रही है। उसका पार्टी घोषणा पत्र लागू होने के बजाय प्रदेश में ब्लैकमनी का पहाड़ प्रभावशील है। वहीं राज्य में बीजेपी का पूरा कुनबा इस समय मौजूदा सरकार को घेरने

छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष लगभग 05 हजार करोड़ का है अवैध शराब कार्टल टैक्स, ईडी कर रही है गिरफ्तारी की तैयारी

देश में शायद छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां पर उसने शराब का एक अवैध कार्टल टैक्स विकसित किया जिससे प्रतिवर्ष लगभग 05 हजार करोड़ तक की आमदनी कार्टल के रास्ते से ऊपर तक पहुंचती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगभग 700-800 शराब सरकारी दुकाने हैं जहां पर शराब की बिक्री होती है। छत्तीसगढ़ में शराब बेचना सरकार के हाथों में हैं। इसका खुलासा कुछ हद तक आयकर विभाग की फरवरी 2020 की शराब सेन्ट्रिक रेड छत्तीसगढ़ में कई जगह हुई। छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों में एक कार्टल विकसित किया गया उदाहरण के तौर पर अगर प्रतिदिन 100 शराब की बॉटल बिकती है तो केवल 50 शराब की बॉटल की बिलिंग होती है। अर्थात आधे पैसे सीधे कार्टल के खाते में पहुंचते थे। शराब में एक्साईज ड्यूटी ज्यादा होती है जैसे 100 रूपये की बॉटल पर सीधे–सीधे 50-60 रूपये इस अवैध तंत्र के पास जाते थे। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा शराब से अलग तरह का खेल भी खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ राज्य बीव्रेज कॉर्पोरेशन जो छग में किस ब्रांड की शराब की बिक्री की जाना है यह निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर देश में 15-20 प्रतिष्ठित बियर ब्रांड बिकती है पर इनमें से छग में 2 या 3 ब्रांड की बिक्री की जाती है। वह भी स्थानीय स्तर की डिसलरी सीधे इस कार्पोरेशन और अवैध शराब कार्टल को सेट करके पूरे प्रदेश में अपनी ब्रांड की बिक्री करती है। इसके अलावा छग में गांवो में जहां शराब की दुकाने नहीं होती वहां पर अवैध शराब जिसे कोचिना गिरी कहते है। यह पूरा ऑपरेशन इस अवैध शराब कार्टल के पास है। इसी से आधारित आयकर विभाग ने देश में पहली बार एक आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1183/2022 तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में दर्ज किया जिसमें अनिल टुटेजा, यश टुटेजा (अनिल टुटेजा के पुत्र), सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर (इस पूरे शराब कार्टल के किंगपिंग है एवं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बडे भाई है), नितिश पुरोहित, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, सीऐ विकास अग्रवाल, मंदीप चावला उर्फ मेंडी (यश टुटेजा के बिजनस पार्टनर कहा जाता है कि कृषि से संबंधित बडा ठेका इन्हीं को मिलता है।), लिंगराज सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड, सौरभ जैन, वैभव सलूजा (लिंगराज सप्लायर प्रा.लि. के पूर्व डायरेक्टर), अशोक कुमार अग्रवाल (लिंगराज सप्लायर प्रा.लि. के डायरेक्टर), गरिमा शर्मा, स्वाति अग्रवाल एवं निशी अग्रवाल अभियुक्त बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद दो प्रमुख कार्टल विकसित किय गये जिसमें पहला कार्टल कोयला, लौह से अवैध कमाई को लेकर था और इसकी किंगपिग सौम्या चौरसिया और उसके सहयोगी सूर्यकांत तिवारी थे और दूसरा कार्टल जो कि शराब के अवैध कमाई को लेकर विकसित किया गया जिसके किंगपिंग अनवर ढेबर है जोकि अनिल टुटेजा के खास है। अनवर ढेबर को हाल फिलहाल दो बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुला चुकी है साथ ही इनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत प्रकरण में भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जनवरी के बाद इनके मामले में और तेजी आयेगी और छत्तीसगढ राज्य में 20 हजार करोड़ की अवैध कमाई शराब घोटाले का पर्दाफाश हो। ईडी द्वारा अवैध शराब कार्टल को बेनकाब करते हुये अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, ए.पी. त्रिपाठी एवं छत्तीसगढ़ में शराब कार्टल से संबंधित व्यवसायियों को नोटिस देकर पूछताछ की। जल्दी हो सकती है इन लोगो की गिरफ्तारी।

में लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे, केदार कश्यप, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, रामविचार नेताम, सरोज पांडे, धरमलाल कौशिक जैसे

छत्तीसगढ़ में अब भ्रष्टाचार के महागुरु बढ़ाएंगे सरकार की मुसीबत काली कमाई का वीडियो आया सामने

छत्तीसगढ़ में आयकर और ईडी के छापों से राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारा गरमाया हुआ है। कई वरिष्ठ अफसर जाँच के घेरे में है। आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई ईडी की रिमांड पर है। कई अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की काली करतूतों पर ईडी की निगाहें गड़ी हुई हैं। सत्ता के मुख्यालयों से जुड़े कई कारोबारियों और अफसरों को पूछताछ के लिए रोजाना आईटी-ईडी के दफ्तर में हाजिरी बजानी पड़ रही है। भ्रष्टाचार और योजनओं में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार की फजीयत अलग हो रही है, उसकी साख दांव पर है। इस बीच एक खूफिया कैमरे और मोबाईल से लिया गया, एक-दो वीडियो चर्चा में आया है।

कई बड़े नेता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डॉ. रमन सिंह के हमलावर रुख ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी समेत मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। यही नहीं, उनके विश्वासपात्र अफसरों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कठघरे पर खड़ा किया

सीन नंबर- 1 ये वीडियो सरकार की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफी कारगर बताया जा रहा है। इस वीडियो में महागुरु के दरबार में तैनात दो कुख्यात वसूलीबाज़ नुरू और पंड एक ठेकेदार से मोटी रकम लेते साफ़ नजर आ रहे हैं। पहला वीडियो करीब साढ़े तीन मिनट का है, इसमें नुरू ठेकेदार का हालचाल पूछते हुए एक थैलाङ्क्तबैग हाथ में थामते हुए हालचाल पूछ रहा है। लाल शर्ट पहने ठेकेदार जी विभाग के हालचाल से उसे रूबरू करा रहा है। गुरुघंटाल से हुई बातचीत का हवाला देते हुए नुरू किसी ईएनसी का नाम लेते हुए, आरजी साहब का गुणगान में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ-कुछ बोलता नजर आ रहा है। वीडियो के पहले हिस्से के करीब 2 मिनट 42 सेकेंड में के इस वीडियो में 02 हजार के नोटों की गड्डी को पहले एक टेबल में रख उसे अखबारी कागजो में पैककर रंग बिरंगे पतले कपड़े वाले डिस्पोजल बैग में रखते दिखाया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार के मिशन पर ये सभी डटे नजर आ रहे हैं।

सीन नंबर- 2 करीब 04 मिनट 16 सेकेण्ड के इस वीडियो में किसी भीतरी कक्ष की सजावट काफी अच्छी नजर आ रही है। गुरु घंटाल बाबा की तस्वीरों और ट्राफी से कक्ष का सौंदर्य निखर रहा है। वही एक टेबल-कुर्सी के पास खड़ा शख्स सम्भवता वीडियो बनाने वाले से ही बातचीत करता नजर आ रहा है। अन्य दो लोग उसके अगल-बगल से हाथो में कुछ लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में किसी कार्यक्रम में सिरकत करने वाले नेताजी के बारे में सवाल पूछने की आवाज आ रही है, तभी वीडियो में कैद शख्स बाएं सिर घुमाकर मुख्यमंत्री और बाबाजी के आगमन के रूपरेखा से अवगत करा रहा है। इस वीडियो की आवाज में सेकेण्ड-सेकेण्ड की रूकावट के चलते तीन बार खींच-खींच का स्वर है, लेकिन सामने खड़े शख्स का पूरा हुलिया दिखाई दे रहा है। इसे ही पंडा नामक प्रमुख वसूलीबाज़ बताया गया है। बातचीत से साफ़ समझा जा सकता है कि पंडा से लगातार बातचीत के दौरान बार-बार सर-सर कर हामी भरी जा रही है। यह शख्स कोई वरिष्ठ अफसर है, जबकि उसके साथ खड़ा सफ़ेद शर्ट में कोई कारोबारी या ठेकेदार है। कुछ लोग इसका नाम धमतरी आरजी का पप्पू बताते हैं। पप्पू पूरे विभाग में चर्चित है। तमाम सीई से उसका लेन देन का रिश्ता बताया जाता है। इस वीडियो में भी किसी बालगोपाल के 18 के आंकड़े को लेकर साफ़-साफ़ बात हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पंडा इस झोले में रखी मोटी रकम को कैसे हाथो -हाथ ले रहा है। ईएनसी और इस सीई का नाम लेते हुए कमीशन का खुला खेल कैसे खेला जा रहा है, दाम और काम के आंकड़े गुरु घंटाल की असलियत जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो की दास्तान वाकई हैरतअंगेज है।

सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो किसी ठेकेदार ने अपने ग्रुप में डाला था। इसमें बताया गया था कि केंद्रीय एजेंसियों को यह अनकट, इसके आलावा ऐसे ही कुछ अन्य ऑडियो-वीडियो अलग-अलग शिकायतकर्ताओं ने सौंपे हैं। हालांकि जगत विजन पत्रिका ऐसे किसी ऑडियोङ्क्तवीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। एक व्हाट्सअप ग्रुप में प्राप्त इस वीडियो को जैसा देखा वैसा लिखा, की तर्ज पर पाठकों को यह समाचार पेश किया है।

गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार के साढ़े 04 साल के कार्यकाल में अब तक कांग्रेस सरकार एक आरोप भी रमन सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ सिद्ध नहीं कर पाई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान सत्ता पाने के लिए क्या कांग्रेस ने झूठ बोल गुमराह किया था। यही हाल उन अफसरों का है, जो बीजेपी के दौर में चर्चित रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के

झुझलाहट में भूपेश बघेल ने सतनामी समाज (अजा) को शाम को भौंकने वाला अर्थात कुत्ता कहा

कहते है ना तीर एक बार कमान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आता वैसे ही मुख से निकली हुई वाणी वापिस नहीं आती। अब एक ऐसा ही वाणी रूपी तीर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख से सतनामी समाज के विरूद्ध निकल गया था। दरअसल भूपेश बघेल मुंगेली जिले में आयोजित बाबा घासीदास जी के जयंती कार्यम में मुख्य अतिथि बनकर शामिल हुए थे। जब मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान सतनामी समाज के युवकों ने बैनर-पोस्टर लहराकर आरक्षण मामले पर विरोध कर मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद भूपेश बघेल ने सतनामी समाज के लिए एक टिप्पणी कर दी और कहा कि शाम को कौन भौंकते हैं, मालूम है और जो शाम को भौंकते हैं, उनसे हम नहीं डरते। बड़ा सवाल ये है कि भूपेश बघेल ने आखिर पूरे अनुसूचित जाति समाज (सतनामी समाज) को भौंकने वाला घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री ने पद की मर्यादा को तोड़ते हुए एक समाज को शाम होते कौन भौंकते वाला कुत्ता कह दिया है। यह कार्यक्रम बाबा घासीदास जयंती पर आयोजित था, जिनके अमर वाक्य मनखे मनखे एक समान, कह गए गुरु घासीदास महान जिन्होंने सतनामी समाज को आगे बढ़ने की बात की। ऐसे में भूपेश बघेल ने सतनामी समाज और गुरु घासीदास जी का भी मान नही रखा और उनके अंदर का विष इस समाज के लिए बाहर निकल आया। खैर यह अपमान की भरपाई निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को भुगतना होगा।

नेता और मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस के तमाम आरोप इन 04 वर्षो में मिट्टी में मिल गए। बताया जाता है कि पार्टी और सरकार दोनों ही अपने किसी भी आरोपों को लेकर गंभीर नजर नहीं आई है। इधर कांग्रेस ने अपने पूरे साढ़े 04 साल के कार्यकाल में सिर्फ मुख्यमंत्री रमन सिंह को कोसने में वक्त गुजार दिया। इन वर्षो में कांग्रेस के कई नेताओं और प्रवक्ताओं की राडार पर सिर्फ

मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनका परिवार ही रहा। रमन सिंह के अलावा इन वर्षो में उनके मंत्रीमंडल के किसी भी मंत्री के खिलाफ कांग्रेस सरकार को एक तिनका तक हासिल नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर ही कांग्रेस अपने राजनीतिक शिगूफे छोड़ते रही। वही बीजेपी अपने बचाव में जुटी रही। हालाँकि अब वक्त आ गया है जब प्रदेश की जनता कांग्रेस के साढ़े 04 साल और बीजेपी के 15 सालों के कामकाज का आंकलन कर रही है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर आये दोनों ही सरकारों के अंतर को उसने महसूस करना भी शुरू कर दिया है। राज्य की जनता कांग्रेस के तमाम हवाहवाई हमलों को बखूबी देख रही है। वो यह भी देख रही है कि आईटी-ईडी के छापों से क्या निकल रहा है।

छत्तीसगढ़ सीएम बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ ब्यूरोट सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी समीर विष्णोई और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लैवी वसूलने का है। यह आशंका जताई जा रही है कि 16 महीनों में 500 करोड़ रुपये यहां से वहां किए गए। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने चौरसिया को राज्य में कथित कोयला ढुलाई घोटाले में धन शोधन की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया। राज्य की

शक्तिशाली नौकरशाह मानी जाने वाली चौरसिया को संघीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को स्वास्थ्य जांच के लिए

सत्ता के दलालों के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आईएएस, आईपीएस अफसर

लालफीताशाही में एक कहावत आम रहती है कि सत्ता के पास रहो तो मलाई खाने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में इस मलाई को खाने के चक्कर में प्रदेश के आईएएस और आईपीएस को जेल की सूखी रोटी खाने की नौबत आ गई है। दरअसल ईडी द्वारा माईनिंग कार्पोरेशन के पूर्व संचालक समीर विश्नोई को जब गिरफतार किया उसके बाद मानो प्रदेश में हड़कंप सा मच गया। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस जिस प्रकार सत्ता के दलाल जैसे सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया की गुलामी करते थे और उनके कहने पर हर गलत काम करने को तैयार हो जाते थे। कहते है न बुराई का अंत खराब ही होता है। वैसे ही इस दुष्चक्र का अंत तो होना ही था। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए एक व्यक्ति को कितनी मेहनत करना पड़ता है, साथ-साथ पूरे परिवार को भी कुर्बानी देनी पड़ती है तब जाकर एक सामान्य अभियर्थी आईएएस, आईपीएस बन पाता है।

छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस सरकार बनी तबसे इन अधिकारियों में सत्ता की मलाई खाने को लेकर होड़ सी मच गई। जिसके लिए इन्होंने हर तरीके के गलत काम करने से भी इन्होंने गुरेज नहीं किया। पैसा और पॉवर का एक ऐसा नशा इन लोगों के सिर पर चढ़ा कि यह लोग अपनी मेहनत और बलिदान के दिन भी भूल गए। आज समीर विश्नोई जैसा अधिकारी जेल की चार दीवारी में बैठकर अपने आपको जरूर कोसता होगा। आगे प्रदेश के दो आईएएस रानू साहू और उनके पति भी गिरफ्तार होने को बैठे हैं। इन सत्ता के दलालों का साथ शुरूआत में तो अच्छा लगता है पर बाद में दम सा घुटता है जिसका उल्लेख ईडी की चार्जशीट में पेज क्रमांक 60 से लेकर 68 में समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी और समीर विश्नोई की पत्नी की चैट को दर्शित किया गया है। सूर्यकांत तिवारी द्वारा सीएम और मेडम सौम्या चौरसिया के नाम पर समीर विश्नोई को कई बार धमकाया गया। इस पूरे वार्तालाप में एक आईएएस अधिकारी किस तरह घबराया हुआ रहता है और बाद में इसी तनाव में अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं, उससे प्रदेश के ऐसे आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की मनोस्थिति समझ में आती है। इन दलालों से ब्लैकमेल होकर हर तरह के गलत-सलत काम इन लोगों को करना पड़ रहा है। 2023 में कांग्रेस सरकार जाने तक कम से कम 10 आईएएस/आईपीएस अधिकारियों पर लटकेगी बर्खास्तगी की तलवार।

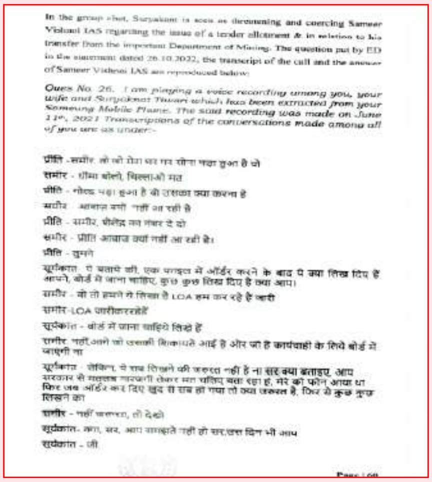

In the group chat, Suryakant is seen as threatening and coercing Sameer Vishnoi IAS regarding the issue of a tender allotment & in relation to his transfer from the important Department of Mining. The question put by ED in the statement dated 26.10.2022, the transcript of the call and the answer of Sameer Vishnoi IAS are reproduced below:

Ques No. 26. I am playing a voice recording among you, your wife and Suryakant Tiwari which has been extracted from your Samsung Mobile Phone. The said recording was made on June 11th, 2021 Transcriptions of the conversations made among all of you are as under:-

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में समीर विश्नोई अपने पत्नी के साथ तनाव में रहने का उल्लेख करते हुये।

ले जाया गया। ईडी ने अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई और दो अन्य लोगों को मामले में कई छापे मारने के बाद गिरफ्तार किया था।

नौकरशाहों, व्यवसायी और नेता का

बस्तर की 17 सीटों पर कांग्रेस की हालत खराब

बस्तर संभाग की लगभग 17 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। इस संभाग में आदिवासियों का काफी वर्चस्व है। यादातर सीटों पर आदिवासी ही हार-जीत का फैसला करते हैं। चूँकि जब 2018 में प्रदेश में आम चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही प्रदेश में पेसा कानून लागू किया जायेगा। अब जब सरकार को साढ़े 04 साल हो गए हैं लेकिन पेसा कानून पूरे तरह लागू नही किया है। जो किया है वह आधा-अधूरा है। कह सकते हैं कि तोड़-मरोड़ कर लागू किया है। इससे इस संभाग में कांग्रेस को भारी नुकसान होने की संभावना है।

गठजोड़- ईडी द्वारा आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई धन शोधन की जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसायी, नेता और बिचौलिए के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से बातचीत में ईडी पर अपना हमला तेज करते हुए जांच एजेंसी पर अपनी हद पार करने और राय में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

कहीं भूपेश बघेल पर भारी न पड़ जाये सौम्या चौरसिया

सौम्या चौरसिया के जेल जाते ही छत्तीसगढ़ की फिजा एकदम बदल गई। मुख्यमंत्री की खासमखास सौम्या और उसकी टीम के सूर्यकांत और पार्टी तो जेल में हैं ही उनके बाद अब आईपीएस अफसर, राजनेता अब ईडी के हत्थे चढ़ने वाले हैं। हालात यह है कि सौम्या के पति सौम्या को बाहर लाने की रोज भूपेश से गुहार लगाते हैं। कुछ नही हो पा रहा है। समीर विश्नोई ईडी की कार्यवाही से अभी जेल में है। समीर विश्नोई की पत्नि अपने पति को छुडवाने के लिए प्रतिदिन भूपेश बघेल से मिलने जाती है। लेकिन बताया जाता है कि बघेल ने अब उनसे मिलना ही बंद कर दिया है। भूपेश बघेल अब तो यह भी कहने लगे हैं कि मैंने थोड़ी कहा था कि भ्रष्टाचार करो। लेकिन सब जानते हैं कि समीर जैसे भ्रष्टाचारियों को शह किसने दी थी। सौम्या ने भी अंदर से धमकी दे दी है कि में बाहर नहीं आयी तो सबको अंदर पहुंचाउगी। ईडी के पास भूपेश बघेल के खास विनोद वर्मा की युगबोध वाली मनी ट्रेल की जानकारी पहुंच गई है। ऐसे में अभी काफी लोगों का अंदर जाना पक्का है। इसके साथ-साथ ऊपर के दिग्गज के 52 करोड़ की ट्रेल की जैकपॉट भाजपा के पास ईडी के माध्यम से लग गई है। कही ऐसा भी हो सकता है कि सौम्या चौरसिया सरकारी गवाह बनकर भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ा सकती है।

छत्तीसगढ़ की डिजिटल एजेंसी चिप्स में पहली ही झलक में ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला आया सामने, चिप्स की तर्ज पर सरकारी रकम डकार गए अफसर, जांच जारी

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स में पड़े छापों में हैरान करने वाला लगभग ढाई हजार करोड़ का घोटाला सामने आया है। पहले ही झटके में प्राथमिक जांच के दौरान घोटाले की रकम के चढ़ते ग्राफ को देखकर इस रकम के और भी बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा

ईडी ने लिखी डीजीपी (ईओडब्ल्यू और एसीबी) छत्तीसगढ़ को चिट्ठी, जिसमें सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिये गये है। अवैध कोल लैवी टैक्स घोटाले में आईपीसी और पीसी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करने को कहा गया है।

1

प्रवर्तन निदेशालय/Directorate of Enforcement
भारत सरकार/Government of India
क्षेत्रीयकार्यालय / Zonal Office
A-1 ब्लॉक, द्वितीय तल, पुजारी चेम्बर्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)
A-1 Block, 2nd Floor, Pujari Chambers, Pachpedi Naka, Raipur (C.G)
दूरभाष/फैक्स : 0771-2274900 /2274225
Tel. / Fax :0771-2274900/2274225
E-mail : ddrpzo1-ed@gov.in

File No.: ECIR/RPZO/09/2022/1046 Date: 24.03.2023

To,

The Director General of Police,
Economic Offence Wing & Anti Corruption Bureau,
G E Road, Raipur.

Sir/Madam,

Sub: - Sharing of Information against Sh. Sameer Vishnoi, IAS under the provision of Section 66(2) of the PML Act, 2002 in the case of Suryakant Tiwari and others -Reg.

****

It is submitted that based on the FIR bearing No. 129/2022 dated 12.07.2022 registered by Karnataka State Police, Kadugodi PS, Whitefield, Bangalore against Suryakant Tiwari invoking therein section 186, 204, 353, 384 & 120B of IPC, 1860, an ECIR No. RPZO/09/2022 dated 29.09.2022 was recorded against Suryakant Tiwari and Others as Section 384 & 120B of the IPC are schedule offences to the PMLA and investigation under PMLA was initiated by ED, Raipur Zone.

1 | 11 Page

1

प्रवर्तन निदेशालय/Directorate of Enforcement
भारत सरकार/Government of India
क्षेत्रीयकार्यालय / Zonal Office
A-1 ब्लॉक, द्वितीय तल, पुजारी चेम्बर्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)
A-1 Block, 2nd Floor, Pujari Chambers, Pachpedi Naka, Raipur (C.G)
दूरभाष/फैक्स : 0771-2274900 /2274225
Tel. / Fax :0771-2274900/2274225
E-mail : ddrpzo1-ed@gov.in

File No.: ECIR/RPZO/09/2022/1045 Date: 24.03.2023

To,
The Director General of Police,
Economic Offence Wing & Anti Corruption Bureaue,
G E Road, Raipur, Chhattisgarh.

Sir/Madam,

Sub: - Sharing of Information against Smt. Saumya Chaurasia under the provision of Section 66(2) of the PML Act, 2002 in the case of Suryakant Tiwari and others -Reg.

****

It is submitted that based on the FIR bearing No. 129/2022 dated 12.07.2022 registered by Karnataka State Police, Kadugodi PS, Whitefield, Bangalore against Suryakant Tiwari invoking therein section 186, 204, 353, 384 & 120B of IPC, 1860, an ECIR No. RPZO/09/2022 dated 29.09.2022 was recorded against Suryakant Tiwari and Others as Section 384 & 120B of the IPC are schedule offences to the PMLA and investigation under PMLA was initiated by ED, Raipur Zone.

2. That, searches were conducted under PMLA at various premises of Suryakant Tiwari and his associates and various incriminating documents/digital devices and

1 | 12 Page

है। सूत्रों का दावा है कि चिप्स घोटाले में कई बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एर्जेसियों की छापेमारी में हैरान करने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। बता दें चिप्स घोटाले के चलते आईएएस समीर विश्नोई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। फिलहाल वो ईडी रिमांड में हैं। ईडी की कई टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि ईडी छापेमारी में योजनाओं की आढ़ में फर्जी बिलों के जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी रकम की बंदरबांट हो रही थी। बगैर किसी कार्य के अंधाधुंध चेक काटे जा रहे थे। एक शक्तिशाली बंगले में तैनात प्रभावशील अफसरों के नाम पर कई एंट्री पाई गई है। सूत्र बता रहे हैं कि चिप्स की सरकारी रकम को मिलजुल कर आलू चिप्स समझ कर खाया जा रहा था। इसमें फाइबर ब्लॉक पर हुए कार्यो के नाम पर 15 सौ करोड़ से यादा के भुगतान से जुड़े दस्तावेजों के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत नेट परियोजना का भुगतान का लगभग पूरा हिस्सा अधिकारियों ने डकार लिया। बगैर एसओपी का पालन किए तमाम प्रिया अपनाई गई थी। टाटा प्रोजेक्ट के कार्यो को लेकर 400 करोड़ की पेनाल्टी में से 200 करोड़ का भुगतान बगैर किसी ठोस आधार के किया गया।

बताया जाता है कि आईडिमिया प्रोजेक्ट में 121 करोड़ के भुगतान में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें भुगतान के दौरान कंपनी के साथ 10 करोड़ का लेनदेन किया गया था। सरकारी तिजोरी में हाथ साफ़ करने के लिए इस कंपनी ने चिप्स के कुछ आलाधिकारियों की फैमिली ट्रिप स्पॉन्सर्ड कराई थी। भ्रष्टाचार की रकम से अफसरों के परिवारो ने भी टूरिस्ट प्लेसो का जमकर लुत्फ़ उठाया। इम्पेच में बगैर किसी कार्य के

करोडों का भुगतान किया गया। इसके लिए ना तो अनुमोदन लिया गया और ना ही एसओपी का पालन किया गया। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ खानापूर्ति कर करोडों की रकम निकाल ली गई। खनिज ऑनलाइन में ऑडिट एप्लीकेशन जानबूझ कर नहीं कराया गया ताकि घोटालों की रकम का हिसाब-किताब सामने ना आ सके। जानकारी के मुताबिक नीलेश नामक शख्स एसईएमटी कर्मी को वाइंट सीईओ बनाकर अपराध को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नीलेश की नियुक्ति इस पद पर गैर कानूनी रूप से की गई ताकि आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया जा सके। बताया जाता है कि जिस दिन समीर विश्नोई के यहाँ छापा डाला गया था, उसी दिन सुबह नीलेश ने 15 स्वीट के पैकेट में मोटी रकम रखकर एक ख़ास ठिकाने में भेजा था। इस रकम के प्रमाणिक सबूत भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक घोटाले की रकम और उससे जुड़े कई दस्तावेजों को आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई के फार्म हाउस से भी बरामद हुए हैं। इसका सीधा लिंक नीलेश से जुड़ा पाया गया है। सूत्रों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि समीर विश्नोई की ब्लैक मनी को धनशोधन के लिए प्रतिक और राजेंद्र कई स्रोतों तक पहुंचाते थे। इस रकम से चल-अचल संपत्ति की खरीदी का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि चिप्स के अन्य कई जिम्मेदार अफसरों के आईटीआर खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक समीर विश्नोई की पत्नी प्रीति विश्नोई के लिए नीलेश ने एक नया मोबाइल फोन ख़रीदा था। बताया जा रहा है कि चिप्स के भ्रष्टाचारों की लम्बी फेहरिस्त इस मोबाइल में दर्ज है। इसका ब्यौरा प्रदेश में राजनैतिक भूचाल ला सकता है। दरअसल बताया जा रहा है कि विश्नोई दंपत्ति के तार एक शक्तिशाली बंगले से सीधे तौर से जुड़े पाए गए हैं। लिहाजा केंद्रीय जांच एर्जेसियां इस बड़े सुनियोजित भ्रष्टाचार की जांच गंभीरतापूर्वक एवं पेशेवर तरीके से कर रही हैं।

क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा?

सूरत की अदालत से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में सर्वोच्च सजा अर्थात दो साल की सजा हुई, पर उनको आगे अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत भी दी। सजा मिलने के 48 घंटे के भीतर राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दो वर्ष या उससे ऊपर की सजा में सांसदी या विधायकी जाती है। कुल मिलकर इतने संयोग हुए जिससे पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। आजाद भारत में पहली बार किसी नेता को भाषण के कारण सजा और संसद सदस्यता गई है।

विजया पाठक

दिनांक 24 मार्च 2023 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय में से एक माना जायेगा। नए भारत के इस अघोषित आपातकाल में क्या विपक्षी दलों से सवाल नहीं पूछने देंगे। चुनावी भाषणों के आधार पर आपराधिक मानहानी किसी दूसरे व्यक्ति से लगाई जाएगी और सजा दिलाकर आपको अपनी बात रखने जनता ने जो प्लेटफार्म दिया है वो भी छीन लिया जाएगा। दरअसल इस हाईटेक ज़माने का लोकतंत्र में अब सत्ताधारी दल या उसके नेता के खिलाफ बोलने, लिखने या देखने पर बैन है। अभी हाल ही में बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री देशभर में बैन कर दी गई। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के पहले वो भाजपा राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती थी पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिले जनता के सपोर्ट से भाजपा का नजरिया बदल गया। अडानी-नरेंद्र मोदी संबंधों के ऊपर आक्रामक राहुल गांधी की लंदन व्याख्यान

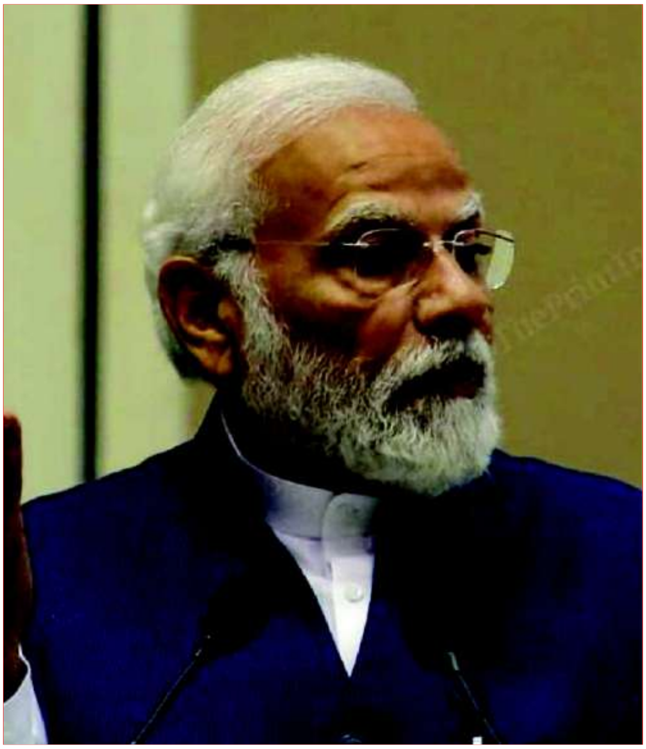

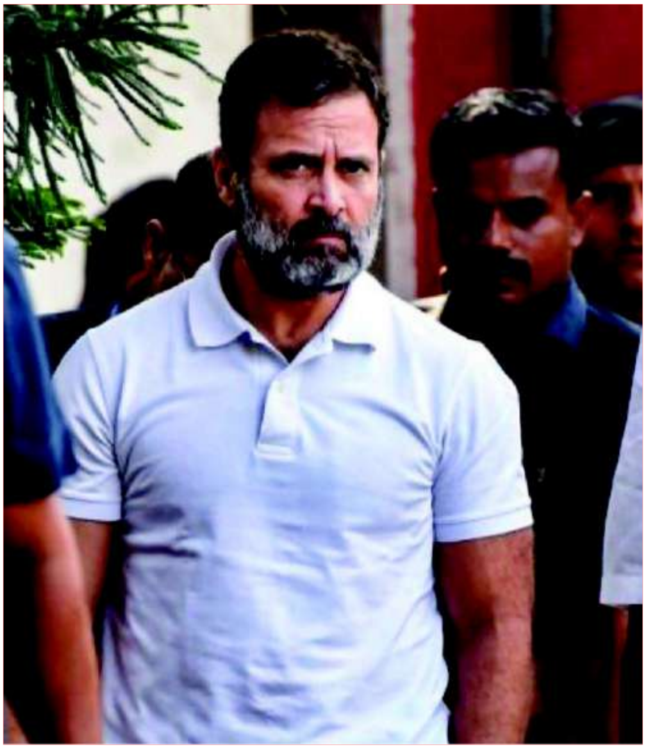

से देश में भाजपा के लगभग हर नेता ने कोस-कोस कर देश की बदनामी का तमगा उनको पहनाने की कोशिश की और कमोबेश जो बात वो वहां बोलकर आए वही बात अब चरितार्थ सिद्ध हो गई है।

इतने सारे संयोग से सजा का मार्ग प्रशस्त

दिनांक 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार से चुनावी रैली में एक भाषण दिया और जनता से प्रश्न पूछा कि जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी को लेकर बोला कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों है? इसके बाद 16 अप्रैल 2019 को गुजरात सरकार के पूर्वमंत्री और सूरत से विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 से राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक मानहानि का मामला सूरत की अदालत पर दाखिल किया गया। अपनी ही मानहानि पिटीशन पर पिटीशनर पुर्णेश मोदी 2022 में गुजरात हाईकोर्ट से

क्या मानहानि और भ्रष्टाचार समेत अन्य आपराधिक कृत्य को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबर माना जायेगा?

स्टे ले आए। फरवरी 2023 में पिटीशनर पुर्णेश मोदी पुनः हाईकोर्ट गए और अपने लगाए स्टे का खात्मा करवा लिया। सूरत की अदालत से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में सर्वोच्च सजा अर्थात दो साल की सजा हुई, पर उनको आगे अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत भी दी। सजा मिलने के 48 घंटे के भीतर राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दो वर्ष या उससे ऊपर की सजा में सांसदी या विधायकी जाती है। कुल मिलकर इतने संयोग हुए जिससे पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। आजाद भारत में पहली बार किसी नेता को भाषण के कारण सजा और संसद सदस्यता गई है।

शाहीन बाग में दिल्ली हाईकोर्ट की थी टिप्पणी- चुनावी भाषाओं को लाईटली लेना चाहिए

शाहीन बाग मामले में जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों को को लेकर लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए तो अदालत ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया चुनावों में दिए भाषण सामान्यता आम दिनों से अलग रहते हैं, कई बार माहौल बनाने के लिए ऐसे भाषण दिए जाते

यह लोकतंत्र की हत्या है- कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, मप्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी के खिलाफ षडयंत्र करने में सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षडयंत्र स्व. इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकन उससे इंदिरा जी मजबूत ही हुई थीं, कमजोर नहीं। आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी है, इंसाफ होकर रहेगा। कमलनाथ ने कहा कि घर थोड़े ही ना बैठेंगे। राहुल गांधी पूरे देश में दौरा करेंगे। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और उनके चहेते खरबपति लोगों के संबंधों को उजागर करेंगे। मोदी जी विदेशों में जमा कालाधन वापस लाओ या गद्दी छोड़ो। लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन पर आोश जताया है।

हैं जिसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसके आगे माननीय अदालत ने यह भी टिप्पणी की अगर यह बात हंसकर की गई है तो कोई मामला नहीं बनता है। वैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ हर पार्टी के नेता कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। जैसे कि इटली वाली, मंदबुद्धि, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कपड़े पहनकर नहाना, यह तो स्वयं मोदी जी के कुछ चुनिंदा चुनावी शब्द थे। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को कपटनाथ और झूठनाथ कहा। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ को भ्रष्टाचारी और लूट खसोटी करने वाला कहा। भाजपा नेताओं की बदजुबानी पर तो

500 पन्नों की किताब लिखी जा सकती है। बात समझने की यह है कि लोकतंत्र में तो नेता बोलकर ही कोई अपना विरोध दर्ज करता है। पर आज भारत में अलोकतांत्रिक तरीके से चुप कराने के लिए मानहानि जैसे गैर-आपराधिक कृत्य को आपने आपराधिक कृत्य वाले नेताओं की लाइन में ही लगा दिया। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही 2019 में भाजपा के विधायक को आपराधिक मामले में सजा होने पर विधायकी से बर्खास्त करने पर, कांग्रेस सरकार को शिवराज सिंह चौहान आलोकतांत्रिक घोषित कर दिया था और 02 मिनिट का वीडियो जारी किया था। आज भारत की इस मामले में दुनिया भर में भर्त्सना की गई है।

किस दिशा में जा रहा है हमारा लोकतंत्र

संसद के भीतर अब ऐसी स्थिति आ गई कि विपक्षियों को बोलने नही दिया जा रहा है। डाक्यूमेंटेशन देने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनका जबाव सरकार नहीं देती है। सब पूछना चाहता है कि संसद में सवाल करना कौनसा गुनाह है। मोदी सरकार को राहुल का सवाल पूछना ही गलत लगता है। इतिहास जरूर पूछेगा कि संसद में सवाल पूछने से क्यों रोका गया है। संसद में उनके पूरे भाषण को हटा दिया जाता है। आज राहुल गांधी पर हुई कार्यवाही से पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। सही मायनों में कहा जाये तो इस कार्यवाही से पूरे विपक्ष को एक होने का अवसर दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दोष यही था कि देश से भाग गए भगोडों के नाम उन्होंने भरी सभा में पुकारे थे। लेकिन यह असली सवाल नहीं है। यह सवाल व्यक्ति राहुल गांधी तक सीमित है। यह सवाल उस प्रवृत्ति तक नहीं जाते जिसके केंद्र में राहुल गांधी नाम का व्यक्ति है। उस प्रवृत्ति को समझने के लिए नए जमाने की तानाशाही और उसे लागू करने के अत्याधुनिक औजारों को

गौर से देखना होगा। सारा खेल इस बात का है कि कोई भी तानाशाह, सत्ता हमेशा के लिए अपने हाथ में चाहता है और उसके लिए हर वह हथकंडा अपनाता है जिससे उसकी सत्ता मजबूत होती है और हर उस संस्था को कमजोर या बर्बाद कर देता है जो उसके साथ सत्ता की हिस्सेदारी करना चाहती है। भारत में सत्ता पाने का सीधा माध्यम चुनाव में जीत हासिल करना होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत होती है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए या यूं कहें उसे अपने कब्जे में लिया जाए।

आज वर्तमान में गौर से देखा जाए तो लोकतंत्र का दमन करने के लिए यही हथकंडे पूरे देश में अपनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी इसके ना तो पहले शिकार हैं और ना ही आखरी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ाकरे, केएसआर सब के ऊपर यही हथकंडे अपनाए गए हैं। फर्क बस इतना है कि किसने अपना दामन किस हद तक बचा कर रखा है और उसकी राजनैतिक वजनदारी कितनी है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी इन सभी नेताओं में सबसे यादा वजनदार है। वे इनकम टैक्स से नहीं डरे, सीबीआई से नहीं डरे, ईडी की 60 घंटे तक चली पूछताछ से नहीं डरे, एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने से नहीं डरे, उनके खिलाफ वर्षो से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान से नहीं डरे, देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ की तिजोरी से नहीं डरे और तानाशाह से आंख में आंख मिलाकर संसद और सड़क पर उसका कच्चा चिट्ठा खोलने से नहीं डरे। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जा रही है। लेकिन असल बात तानाशाही से संघर्ष की है। जब कोई तानाशाह गद्दी पर बैठता है, तो मीडिया, गोदी मीडिया बन जाता है, संवैधानिक प्रयिा कांस्टीट्यूशनल हार्डबाल बन जाती हैं और पूरा लोकतांत्रिक ढांचा शरीर से लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति तानाशाही की हो जाती है। पुलिस चोर को नहीं पकड़ती, फरियादी को पकड़ती है। अदालत अपराधी को दंडित नहीं करती, फरियादी से सवाल करती है। न्याय की मूल भावना मर जाती है और प्रयिा ही कानून बन जाती है। जुल्म को न्याय की तरह प्रचारित किया जाता है।

विदेशी मीडिया ने भी राहुल गांधी पर हुई कार्यवाही को कवर किया

राहुल गांधी आवाज को दबाने की कोशिश की लेकिन अब दुनिया के हर कोने में भारत की आवाज सुनी जा रही है।/ बता दें कि राहुल गांधी मामले को गार्जियन ऑस्ट्रेलिया, स्पैनिश टेलेमुनडो, जर्मनी के फ्रैंकफर्टर अलेमेने, सऊदी अरब के अशरक न्यूज और फ्रांस के आरएफआई, सीएनएन ब्रासिल आदि विदेशी मीडिया ने कवर किया है। अमेरिकी के भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने भी राहुल गांधी मामले पर टिप्पणी की है और इसे गांधीवादी दर्शन से धोखा बताया है और भारतीय मूल्यों के भी खिलाफ बताया है।

अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा विधानसभा चुनाव

समता पाठक

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट में आमजनों से जुड़े कई मुददों को लेकर फैसले लिए हैं उससे निश्चित ही कांग्रेस को आगामी चुनाव में लाभ होगा। हाल ही में उन्होंने राज्य में ओर जिलों और संभागों का गठन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेण्डर को कीमत कम करने का भी ऐलान किया है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य होगा जहां देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम कीमत पर रसोई गैस सिलेण्डर मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा तो मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद देश के अन्य राज्यों में भी इस मांग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। खासकर मध्यप्रदेश में तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बड़ा मुददा हो गया है। वैसे प्रदेश में कांग्रेस तो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जायेगी। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ महीनों का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस में चल रहा नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा भी खत्म सा

राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ महीनों का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।

हो गया है। यह तय हो गया है कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट ने भी अब मान लिया है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का समय निकल चुका है। इसीलिए उनकी नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी बंद हो गई है। अब सचिन पायलट कहने लगे हैं कि पार्टी के सभी लोगों की एकजुटता से ही अगला विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है।

चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने कस ली है कमर

गहलोत को पता है कि कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते आम जनता में पार्टी के प्रति अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अशोक गहलोत प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत के सोच की झलक इस बार राजस्थान के आम बजट में भी देखने को मिली है। गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट को पूरी तरह आमजन का विकासोन्मुखी बजट बनाया है। बजट में प्रदेश के आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके हित की

अशोक गहलोत प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत के सोच की झलक इस बार राजस्थान के आम बजट में भी देखने को मिली है। गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट को पूरी तरह आमजन का विकासोन्मुखी बजट बनाया है। बजट में प्रदेश के आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके हित की बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका गहलोत पूरा राजनीतिक लाभ उठायेंगे।

बजट में रखा गया है आमजनों का ख्याल

प्रदेश के गरीब लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत ने इस बार के बजट में 19 हजार करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें उजवला योजना में शामिल प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रूपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने व प्रदेश मे खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े एक करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके तहत हर पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध करवाए जाएंगें। जिस पर राय सरकार तीन हजार करोड़ खर्च करेगी। गहलोत की यह योजना 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह व कृषि उपभोक्ताओं को दो हजार यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार की सुविधा देना शामिल है। प्रदेश में सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में युवाओं से अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह बेरोजगार अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। बेरोजगार युवकों के लिए आगामी वर्ष में एक लाख नई भर्तियां करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी लुभाने का काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा तो मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री है। उनकी घोषणा के बाद कई राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करना करने की घोषणा की है। अब हर राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गहलोत ने भाजपा को राजनीतिक रूप से संकट में डाल दिया है। हाल ही में भाजपा शासित कर्नाटक सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना के अध्ययन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी हर चाल बहुत सावधानी से चल रहे हैं। उन्हें पता है कि एक तरफ उन्हें भाजपा सहित अन्य विरोधी दलों से मुकाबला करना होगा। वही पार्टी में व्याप्त अंदरूनी गुटबाजी को भी काबू में कर उन्हें चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाना होगा। तभी उनका चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा।

बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका गहलोत पूरा राजनीतिक लाभ उठायेंगे। गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं, विकलांगो, अनाथ बच्चों को मिलने वाली मासिक

पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर उन्हें बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है। जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही गहलोत ने उक्त सभी लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की थी। अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही साथ ही दो लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परियोजना को केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर पूरा करवाने की बात कही थी। मगर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को आज तक अपने हाथ में नहीं लिया है। इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर सहित इन 13 जिलों में राजस्थान की एक तिहाई से अधिक आबादी रहती है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति तो सुदृ? होगी ही साथ ही उन्हें आने वाले लंबे समय तक पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इन 13 जिलों में विधानसभा की 83 सीट आती है। जिनमें से अभी कांग्रेस के पास 49 और भाजपा के पास 25 सीट है। राजनीतिक रूप से भी इन 13 जिलों में अभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री गहलोत इस नहर परियोजना के मुद्दे पर इस क्षेत्र में अपनी पार्टी की पक? को और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने इस

मुख्यमंत्री बनते ही गहलोत ने उक्त सभी लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की थी। अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही साथ ही दो लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

परियोजना को गति देने के लिए हाल ही में 14 हजार 200 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में भी इस परियोजना के लिए 9 हजार 600 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की थी। इस तरह प्रदेश सरकार ने इस परियोजना पर अब तक 23 हजार 800 करोड रुपए की स्वीकृति जारी कर चुकी है। इससे उक्त परियोजना में नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध, रामगढ़ एवं महलपुर बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज, मेज एनीकट तथा गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने तथा बा? के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकेंगे। इसके साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर बढ़ाने तथा 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा वर्ष 2040 तक जयपुर, अजमेर, टोंक जिले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं तथा जयपुर जिले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16.82 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के कार्य किए जा सकेंगे।

बुंदेलखंड में क्यों काटे जाने हैं 44 लाख पेड़, क्या है सरकार की तैयारी?

हीरे की खदान और केन-बेतवा परियोजना को पूरा करने के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे

विजया पाठक

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इलाके में जहां पहले से ही पेड़-पौधों की संख्या कम हो, लेकिन आने वाले समय में उसी इलाके के 44 लाख पेड़ काटने की तैयारी की जा रही हो। यह इलाका है मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 13 जिलों में फैला बुंदेलखंड क्षेत्र। जो पिछले डेढ़ दशक से सूखे की मार से अभिशप्त है। ऐसे विपरीत हालात में इस इलाके के लाखों पेड़ काटे जाने के बाद क्या यह उम्मीद बच पाएगी कि भविष्य में इस इलाके से सूखा खत्म हो जाएगा?

बुंदेलखंड के बक्सवाहा (छतरपुर, मध्यप्रदेश) के जंगलों में हीरा खदान के लिए चार लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 28 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि अब हर हाल में चार लाख पेड़ काटे ही जाएंगे। एनजीटी ने याचिका को अपरिपक्व करार दिया। हालांकि इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता पीजी पांडे ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश ने बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट व महोबा की सीमा से लगे बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए एक्सेल माइनिंग कंपनी को पेड़ काटने के लिए अभी तक 364 हैक्टेयर भूमि का पट्टा आबंटित किया है।

इस जंगल में केवल पेड़ ही नहीं है, बल्कि यहां के पत्थरों व चट्टानों पर दुर्लभ ऐतिहासकि शैल चित्र भी मौजूद हैं। इनके भी अब नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में एक व्यापक सर्वे किया था और उसमें यह बात निकलकर आई थी कि बक्सवाहा के जंगल में पाषाणकालीन रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। बुंदेलखंड के जिस इलाके में हीरा खनन का ठेका दिया जा रहा है, वहां केवल पेड़ ही नहीं कटेंगे, बल्कि वहां के पत्थरों व चट्टानों पर दुर्लभ ऐतिहासकि शैल चित्र भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस जंगल में कल्चुरी और चंदेल काल की कई मूर्तियां और स्तंभ भी मौजूद हैं, जिनका खनन की वजह से

नुकसान पहुंच सकता है।

यही नहीं, इसी इलाके में केन-बेतवा लिंक बांध परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व के 23 लाख पेड़ काटे जाने की भी तैयारी है। यह बात परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में लिखित तौर पर दर्ज है। यदि इसकी सैटलाइट सर्वेक्षण संख्या को देखें तो लगभग 40 लाख पेड़ काटे जाएंगे।

रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को लागू करने के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को खत्म किया जाएगा। यह वन भूमि 8,427 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। पन्ना के जंगलों में सागौन, महुआ, बेलपत्र, आचार, जामुन, खैर, कहवा, शीशम, जंगल जलेबी, गुली, आंवला समेत अन्य प्रमुख प्रजातियों के बहुत पुराने पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ यहां घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इलाके से इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने के बाद यहां की जैव विविधता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यही नहीं हीरे की परियोजना पर प्रतिवर्ष 53 लाख क्यूबिक पानी भी खर्च होगा। पहले से ही सूखे की मार झेल रहे इलाके लिए यह और भी गंभीर खतरा है। ध्यान रहे कि बक्सवाहा के जंगलों में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरों का यहां दबे होने का अनुमान है। भारत में अभी तक हीरे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है लेकिन बक्सवाहा में तो पन्ना से 15 गुना अधिक हीरे निकलने का अनुमान लगाया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए 2010 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टेंटो की मदद से सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान ही बक्सवाहा के आसपास किंबरलाइट पत्थर की चट्टानें दिखाई दीं।

हीरा इन्हीं किंब्रलाइट की चट्टानों में मिलता है। 2002 में कंपनी को

औपचारिक रूप से क्षेत्र में हीरा तलाशने का काम सौंप दिया गया। लंबे शोध के बाद कंपनी ने खनन की तैयारियां शुरू कीं लेकिन स्थानीय समुदाय के विरोध के कारण कंपनी ने 2016 में इस परियोजना से अपने को अलग कर लिया। इसके बाद 2019 में हीरे की खदान का नया लाइसेंस आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग कंपनी को मिला।

वहीं दूसरी ओर केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस दलील पर आधारित है कि केन नदी में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए दोनों नदियों को जोड़कर केन के पानी को बेतवा में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिल सकेगा। वैसे देखा जाए तो केन और बेतवा दोनों नदियां प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अंत में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, लेकिन सरकार जिस कृत्रिम तरीके से इन्हें जोड़ना चाह रही है, उसे पर्यावरण विशेषज्ञों ने पूरी तरह से विनाशकारी बताया है। सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, जिसमें से मध्य प्रदेश में 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। हालांकि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर प्रचारित की जा रही इस परियोजना के तहत जहां एक तरफ क्षेत्र के 13 जिलों में से आठ जिले (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललिपुर) को ही लाभ मिलने की संभावना है। केन-बेतवा नदी जोड़ों परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना है, जिसमें से पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाएगा, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में डाला जाएगा। दौधन बांध के चलते 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र डूबेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा, जो कि बाधों के रहवास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इस योजना के चलते 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा, जिसमें बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4,141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है।

Inder Malhotra

INDIAN MEDIA

Present tense, Future uncertain

ONE RELIABLE WAY TO FORECAST THE SHAPE OF THINGS to come is to judge the future by the past and by the present. Since the media's currant performance can be a useful pointer, let me give a bird's eye view of what has gone on since the midnight tryst with destiny.

Tryst with destiny.

India is arguably the most political place on earth. Therefore, political reporting-at time tricky, even treacherous-has been the mainstay of journalism throughout most of the era. Things have begun to change but politics is unlikely to lose its primacy. In this respect, my colleague and friend, Harish Khare, now Media Adviser to the Prime Minister, divides the first 60 year of free India into three phases: Age of Nationalism(1947-60), Era of Hones Partisan (1960-75) and the Age of Acrimony (since the Emergency until the present day when the electronic media has

become as important as the print media).

Polarization of Indian polity, media and society has reached its zenith in Indira Gandhi's time and had lasted well after her assassination. Yet, just when it started becoming a thing of the past, political discord between the two mainstream parties, the Congress and the Bharatiya Janta Party, has become so bitter that even elementary democratic norms have been given a go by.

Takeover by the market

Far more dangerous to the media's health has been another development that began towards the end of the 1980s and persists till today. It was the virtual takeover of the media by the market which coincided with the dawn of era of globalization and liberalization as well as with the generational change in the ownership of major newspaper chains.

> **Polarization of Indian polity, media and society has reached its zenith in Indira Gandhi's time and had lasted well after her assassination. Yet, just when it started becoming a thing of the past, political discord between the two mainstream parties, the Congress and the Bharatiya Janta Party, has become so bitter that even elementary democratic norms have been given a go by.**

When a couple of years after Independence, I joined the trade of journalism, newspaper circulations were low (journalists' salaries were ever lower),language used by English newspapers was Victorian and their credibility was high. What startled me at that time was the respect that wealthy newspaper owners showed to their editors even when the latter's writings were inimical to the philosophy and business interests of the firm. By the 1990s. this had changed radically. The editor's authority was eroded to the extent that in some of the most prosperous newspapers, the editor became extinct.

Newspaper-A cake of soap

This was the time when the Berlin Wall fell, the 1990s, the editor's authority was eroded to the extent that in some of the most prosperous newspapers, the editor became extinct. Soviet Union disintegrated, Communism collapsed and the doctrine, according to St. Marx yielded place to the dictates of the St. Market. Despite the governments addiction to globalization, the impact of the market on the media was much greater and graver. It is no exaggeration to say that crass commercial considerations have grievously prevailed over professional values and decencies. For decades, the dividing line between news, comment and advertising has been blurred to the point of disappearances. Editorials in most newspapers are, in reality,

No wonder than that, since then, thanks to flourishing conspiracy between the movers and shakers of the media and the unbidden persuaders masterminding the orgy of commercialism- with the PR agencies acting as brokers- the legitimate quest for profit has turned into reckless and remorseless profiteering. Things did not end theirs, Sensex alone did not dominate the thoughts of newspapers wieners and their henpecked editors.

"advertorials" In one newspaper I worked on, the owners and managers chose to announce that a newspaper was only a "product" like a "cake of soap". I told the arrogant owner that the cake of soap did not have to bother about credibility, objectivity in reporting and finance in comment. He smiled and replied that credibility did you matter. Profit did. A younger colleague wrote a reasoned reply to those dismissing the newspaper as a mere product and found that his rejoinder could be published only as a letter to editor.

No wonder than that, since then, thanks to flourishing conspiracy between the movers and shakers of the media and the unbidden persuaders masterminding the orgy of commercialism- with the PR agencies acting as brokers- the legitimate quest for profit has turned into reckless and remorseless profiteering. Things did not end theirs, Sensex alone did not dominate the thoughts of newspapers wieners and their henpecked editors. Sex did. It

became customary to publish a photograph of the duchess of York sucking her lover's toes on a yacht at the cost of the most important foreign news of the day, When I remonstrated with the editor, he sheepishly replied: "This is what our readers want". May comment: "Then why don't you publish a daily edition of Playboy"? As for the tricks, nearly a hundred TV Channels were playing at the time- gone was the era when they were denounced as "invaders from the skies" the less said the better.

In one newspapers I worked on, the owners and managers chose to announce that a new paper was only a "product"like a "cake of soap"

In one newspapers I worked on, the owners and managers chose to announce that a new paper was only a "product"like a "cake of soap"

During the years preceding the global recession when Sensex soared and the number of Indian billionaires rose to 7,000, something scandalous beyond measure took place. Newspapers stated entering into "private treaties" with flourishing companies. The idea was that the firms would pay for their' ads' not in cash but in their constantly climbing shares. The quid pro quo was that the paper would not only carry positive reports about their treaty partners but also black out any negative or adverse report form whatever source. This worked well unil the Lehman Bank in the US went bust. How the media moguls of India faced the catastrophe in not known.

The stranglehold of the

market on the media has many tentacles. P. Sainath reported some years ago that the 2004 edition of the Lakme Fashion Week produced "some 400,000 words in print, over 1,000 minutes in television coverage, some 800 hours of TV and video footage, and close to 10,000 rolls of film". This, be it noted in a country where less than 0.2 per cent of people sport designer clothes and per capita consummation of textiles at 19 meters in way below the world average.

After the Lok Sabha election in May 2009 and the three assembly polls in Maharashtra, Haryana and Mizoram five months later, it has been exposed that newspapers and TV

channels sold their space and soul to candidates willing to pay generously for election propaganda as news. There were "package prices" for every situation: a candidate could contract for favorablel publicity only or he could also get his opponent trashed. The Adversary also could pay for the same services.

Since then. the disgraceful situation has reached rock bottom. After th Lok Sabha election in May 2009 and the three-assembly poll in Maharashtra, Haryana and Mizoram five months laler, it has been exposed that newspapers and TV channels sold their space and soul to candidates willing to pay generously for election propaganda as news. There were "package prices"for every situation: a candidate could contract for favorable publicity only or he could also get his opponent trashed.The adversary also could pay for the same services. In May, Prabhash Joshi, one of the 'greats' of Indian journalism, who died prematurely the other day, named the proprietors who earned huge money by these dishonest means. But no one, except some professionals troubled by the plummeting standards, seems to have bothered.

P. Sainath reported some years ago that the 2004 edition of the Lakme Fashion Week produced "some 400,000 words in print over 1,000 minutes in television coverage, some 800 hours of TV adn video footage, and close to 10,000 rolls of film".

Against this backdrop, it is difficult to avoid the conclusion that the future of the India media, if not bleak, is surely dismal though it should not be forgotten that, unlike in the West, Indian newspaper circulations are huge and rising. TV Channels are also doing well, if with tacit governmental support in lieu of sycophantic coverage. However, despair should be evaded. In the first place, not every major newspapers of TV channel has fallen prey to unspeakable methods. Sadly though the exponential growth of Hindi chains in the heartland has been accompanied by greed and dishonesty. secondly. there are many professionals who are fighting against all the evil trends. Smaller publications that played a valiant role during the nineteen-month nightmare of the Emergency are busy trying to preserve and protect the values. If we strive hard, the fourth estate can be prevented from being turned into the fourth-rate estate.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.